कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

श्रावण—श्रावण 2080, अगस्त 2023

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

शिवराज सरकार की अनुपम सौगात
सीखना-कमाना अब होगा साथ-साथ

- 46 क्षेत्रों के 800 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण, इनमें विनिर्माण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेल्वे, आईटी, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी, विधि सेवाएं व अन्य सेवा क्षेत्र शामिल।
- 18 से 29 वर्ष के 10वीं-12वीं पास, आईटीआई, स्नातक व स्नातकोत्तर युवा पात्र।
- प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हजार रुपये तक स्टायपेंड।
- 15 जून से पंजीयन एवं 15 जुलाई से प्लेसमेंट।
- पंजीयन के लिए https://mmsky.mp.gov.in/ पोर्टल विजिट करें।

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2023

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

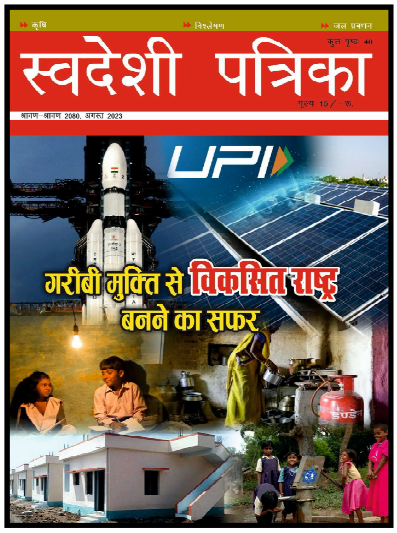

वर्ष–31, अंक–8
श्रावण–श्रावण 2080 अगस्त 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06
गरीबी मुक्ति से विकसित राष्ट्र बनने का सफर
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

09 **आर्थिकी**
हमारी चाल तो ठीक, पर मंजिल बहुत दूर ..... विक्रम उपाध्याय

11 **खोज–खबर**
पढ़े–लिखे लोगों में बढ़ रही है पलायन की प्रवृत्ति ..... अनिल तिवारी

13 **अर्थव्यवस्था**
विनिर्माण से बनेगा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ..... के.के. श्रीवास्तव

15 **पहल**
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ): एक नई पहल ..... डॉ. जया कक्कड़

18 **स्वदेशी**
स्वदेशी सार्वजनिक नीति अनुसंधान का उन्मुखीकरण ..... आलोक सिंह

20 **खेतीबारी**
अपना चावल बचाने की जरूरी पहल ..... देविन्दर शर्मा

22 **अभियान**
भारत का गौरव चंद्रयान–3: एक संक्षिप्त परिचय ..... विनोद जौहरी

24 **मुद्दा**
ऑनलाईन खेलों पर जीएसटी है सही कदम ..... स्वदेशी संवाद

26 **विमर्श**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भारत के आर्थिक विकास पर भरोसा ..... प्रहलाद सबनानी

28 **विश्लेषण**
केंद्र सरकार के प्रयास से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार ..... वैदेही

30 **जल प्रबंधन**
बाढ़ का एक प्रमुख कारण बढ़ता तापमान भी ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

32 **आपदा**
सरकारें पशुओं की भी सुधि ले ..... शिवनंदन लाल

34 **श्रद्धांजलि**
स्वदेशी को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने वाले मदन दास देवी जी

पाठकनामा

स्वदेशी बनाम विदेशी

सरकार स्वदेशी तकनीक के विकास और व्यापार घाटा कम करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने विदेशी लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि इससे भारत में बनने वाले इन उपकरणों की बिक्री बढ़ जाएगी। इनके आयात पर प्रतिबंध संबंधी इस घोषणा के बाद कुछ स्वदेशी कंपनियों के शेयरों में उछाल भी देखा गया। हालांकि यह सरकार का अचानक लिया या कोई बिल्कुल नया फैसला नहीं है, इससे पहले सैकड़ों ऐसी विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, उनमें रक्षा उपकरणों से संबंधित कई चीजें भी शामिल है।

भूमंडलीकरण के जमाने में जब सारी दुनिया एक बाजार में तब्दील हो गई है, लोगों को यह आजादी मिल चुकी है कि वह अपनी पसंद से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कहीं से भी खरीद सकते हैं। यही कारण है कि लोगों की आदतों में विदेशी वस्तुएं शुमार हो चुकी है। लेकिन इसका सीधा असर देश में बनने वाली वस्तुओं पर पड़ता है। घरेलू बाजार में जगह न मिल पाने के कारण स्वदेशी कंपनिया अपने उत्पाद की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार करने में सक्षम नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों की आदतें सुधारने के लिए ऐसे प्रबंध कई बार जरूरी होते हैं।

हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि इस फैसले से विश्व व्यापार नियमों का उल्लंघन होगा और सरकार यह इसलिए कर रही है कि उसका मकसद अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। लेकिन मेरा मानना है कि यह सब विरोध के लिए गढ़े गए बेबुनियाद बातें हैं। सरकार जब चाहे सुरक्षा कारणों को आगे करते हुए किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध लगा सकती है। बावजूद जिन लोगों को बाहर से ऐसी मशीन मंगवाना ही है, उनके लिए कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। बस उन्हें अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल बाहर की वस्तुओं पर रोक लगाने के पीछे सरकार का बड़ा मकसद है कि उसका व्यापार घाटा काफी कम हो जाता है। वर्तमान में भारत निर्यात के मामले में अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसलिए भी व्यापार घाटा को पाटने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि निर्यात को बढ़ाए बगैर अर्थव्यवस्था को लक्ष्य आधारित गति नहीं दी जा सकती।

योगेंद्र सिंह राणा, 26, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

मातृभाषा में शिक्षा भारत में छात्रों के लिए न्याय के एक नए रूप की शुरुआत कर रही है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिमों का एक बड़ा वादा करता है, लेकिन अविश्वसनीय अवसरों का भी वादा करता है।

जो बाईडेन, राष्ट्रपति, अमरीका

भारत का हथकरघा क्षेत्र पूरे विश्व में हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस भारतीय कला को एक बार फिर से नई पहचान देने के लिए देश में सरकार ने हथकरघा दिवस मनाना शुरू किया है।

अमित शाह, गृहमंत्री, भारत

भारत ने दुनिया को यह सबक दिया है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और आवश्यक प्रयासों से बहुआयामी गरीबी को दूर किया जा सकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरणः एक गेम चेंजर

प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में भारत के भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई को शुरू किया गया। देखने में चाहे यह एक छोटी–सी शुरूआत लगती है, लेकिन यह भारत के भुगतान प्रणाली की दुनिया में बढ़ती पहचान का द्योतक है। यूपीआई की शुरूआत 2016 में भारत सरकार द्वारा समर्थित एजेंसी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा की गई थी। यह एक त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसके माध्यम से विभिन्न बैंकों के बीच धन का स्थानांतरण किया जाता है। बड़ी बात यह है कि यह भारतीय रूपए पर आधारित है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबंध में फ्रांस में अपने वक्तव्य में यह कहा कि अब भारतीय फ्रांस के आईफिल टावर से भी रूपए में भुगतान कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए यूपीआई इंटरनेशनल का एक नया फीचर यूपीआई में शामिल किया गया है। जिससे क्यूआर कोड की मदद से भारतीय बैंक खातों से विदेशों में भुगतान किए जा सकते हैं। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और मॉरिशिस में तो पहले से ही यूपीआई से भुगतान संभव था, और अब फ्रांस भी उस सूची में शामिल हो गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में कुल 149.5 लाख करोड़ रूपए के ऑनलाइन लेनदेन हुए। इन लेनदेनों में 126 लाख करोड़ रूपए के लेनदेन सिर्फ यूपीआई के माध्यम से हुए। देश में कुल लगभग 88 अरब ऑनलाइन लेनदेन रिकार्ड किए गए। प्राइस वाटरहाउस कूपर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन भुगतान की संख्या 2026–27 तक एक अरब प्रतिदिन तक पहुँच सकती है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में जितने ऑनलाइन लेनेदेन होते है, उसके 40 प्रतिशत से ज्यादा लेनदेन भारत में होते हैं। बड़ी बात यह है कि 2000 रूपये से अधिक के वैलेट भुगतान पर लगाये गये हालिया शुल्क के पहले, भारत में ऑनलाइन लेनदेन पूर्णतया मुफ्त रहा है। यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण एनपीसीआई के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। 2022 में, एनपीसीआई ने घोषणा की कि वह उन बाजारों में यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए कई देशों में बैंकों और भुगतान कंपनियों के साथ काम करेगा। तब से यूपीआई को कई देशों में लॉन्च किया जा चुका है और कई अन्य मुल्कों में इस हेतु तैयारी चल रही है। उपयोगकर्ता अपने स्थान से अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। व्यापारी व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और भारतीय ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होंगे। यूपीआई सुविधाजनक होने के साथ साथ सुरक्षित भुगतान प्रणाली भी है। आज के साइबर अपराधों के युग में यह एक सुरक्षित भुगतान प्रणाली भी है जो उपयोगकर्ताओं के खातों की सुरक्षा के लिए दो–कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। इसलिए हम देखते हैं कि लेनदेन के इतने बड़े प्रमाण के बाद भी धोखाधड़ी न्यूनतम है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में लागत बहुत अधिक है। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण से सीमा पार भुगतान की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि पिछले साल रूस–यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोपीय प्रणाली 'स्विफ्ट' में अचानक आई रुकावट के बाद यूपीआई को वैश्विक बनाने की मुहिम तेज हो गई है। अमेरिका ने रूस के साथ लेनदेन में सबसे बड़े वैश्विक भुगतान नेटवर्क स्विफ्ट को अचानक रोक दिया था। एक समय था जब पश्चिमी देशों का वित्तीय दुनिया पर शासन था, उनका न केवल अंतरराष्ट्रीय वित्त पर, बल्कि भुगतान प्रणालियों पर भी नियंत्रण था। वैश्विक भुगतान में स्विफ्ट का एकाधिकार था। पश्चिमी देश जब–तब दुनिया को धमकी देते रहते थे कि अगर कोई देश उनके कहे मुताबिक नहीं चलेंगे तो वे उस पर प्रतिबंध लगा देंगे. उनके प्रतिबंधों का मतलब आमतौर पर स्विफ्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को रोकना होता है। अब जब रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, भारत की ओर से भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ कई अन्य क्षेत्रीय ब्लॉक भी अपने सदस्यों की संबंधित घरेलू मुद्राओं में व्यापार के निपटान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पश्चिमी ब्लॉक को ख़ासा अच्छा जवाब मिल रहा है। इससे दुनिया में डी–डॉलरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिल रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में रूपये को अनुमति देने के बाद पिछले एक वर्ष से भी कम की अवधि में 19 देशों ने रूपये में भुगतान लेने के लिए उनके बैंकों द्वारा वोस्ट्रो खाते खोले गये हैं। इस पूरे परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए रूपे और यूपीआई को बढ़ावा देने और विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों में वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति देकर रुपये में व्यापार के निपटान की सुविधा प्रदान करने का भारत का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। घरेलू स्तर पर सिद्ध सफल यूपीआई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी बढ़ती स्वीकार्यता के साथ, भारत को अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में वैश्विक पहचान बनाने के लिए मदद भी मिल रही है।

गरीबी मुक्ति से विकसित राष्ट्र बनने का सफर

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2005–06 में भारत में बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या 64.5 करोड़ थी, जो 2019–21 के दौरान मात्र 23 करोड़ ही रह गई है, यानि पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की चंगुल से बाहर आए। यही नहीं भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2005–06 में 0.283 था, 2019–21 में मात्र 0.069 तक पहुंच गया है। इस बात के लिए यूएनडीपी ने भारत की खासी तारीफ की है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित गरीबी और मानव विकास संबंधी रिपोर्टों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि यूएनडीपी ने भारत की प्रशंसा की हो। यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएनडीपी को भारत की प्रशंसा करनी पड़ी।

शेष दुनिया से भारत की तेज रफ्तार

यूएनडीपी की रिपोर्ट में जिन 81 देशों के गरीबी संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, उनमें शुरूआती आकड़े अलग–अलग सालों के हैं। जिस समय के भी प्रारंभिक आकड़े थे, सभी देशों के गरीब लोगों की सम्मिलित संख्या 150.8 करोड़ थी। चूंकि भारत के आंकड़े 2005–06 से ही उपलब्ध हैं, भारत में तब 64.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित थे। यानि इन 81 देशों के 42.8 फीसदी से ज्यादा गरीब भारत में रह रहे थे। यूएनडीपी के ताजा आंकड़ों के अनुसार इन 81 देशों में गरीबों की कुल संख्या 97.4 करोड़ हो गई है और भारत द्वारा इस संख्या का योगदान मात्र 23 करोड़ का ही है। यानि दुनिया के 81 देशों के गरीबों में अब मात्र 23.7 प्रतिशत ही भारतीय हैं।

इतना ही नहीं, जहां 81 देशों का संयुक्त बहुआयामी गरीबी सूचकांक अब 0.275 से घटकर 0.203 पर आया है, वहीं भारत का सूचकांक 2005–06 में 0.283 से घटकर

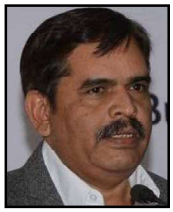

यह दुनिया के लिए एक सबक है। बहुआयामी गरीबी को भी दूर किया जा सकता है, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और आवश्यक प्रयासों की जरूरत है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

2015–16 में 0.122 और 2019–21 में सिर्फ 0.069 पर आ गया है, यानि दुनिया के गरीबी सूचकांक का लगभग एक तिहाई, यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह भारत के लिए गर्व की बात है और दुनिया के लिए सोचने का सबब है। दुनिया को इससे सबक लेने की जरूरत है कि उसे भी भारत की तर्ज पर बहुआयामी गरीबी दूर करने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।

अमृत काल का संकल्प

भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर, अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। पिछले 9 सालों में भारत 2013–14 में दो ट्रिलियन जीडीपी के साथ दसवें स्थान से अब 3.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ पाँचवे स्थान तक पहुँच गया है और प्रति व्यक्ति जीडीपी 1500 डॉलर से बढ़कर लगभग 2500 डॉलर तक तो पहुँची है, लेकिन अमृत काल में भारत का संकल्प है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। लेकिन विकसित राष्ट्र बनने की कुछ शर्तें होती हैं। आज के विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय 35 हज़ार अमरीकी डालर से लेकर 95 हज़ार अमरीकी डालर की है। इसलिए इन देशों हम बहुत पीछे हैं। इन देशों के लोगों की सामान्यतः जीवन की मूलभूत आवश्कताएं पूर्ण होती हैं। गरीबी का आपात नगण्य होता है। वे देश प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भी उन्नत है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी।

क्या मात्र ग्रोथ से घट सकती है गरीबी?

अधिकांश अर्थशास्त्री गरीबी उन्मूलन के बारे में जीडीपी में वृद्धि यानि ग्रोथ को काफी अहमियत देते रहे हैं। यदि देखा जाए तो पिछले लंबे समय से भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती रही है। यदि पिछले 15 सालों का लेखा–जोखा लगाया जाए तो पाते हैं कि भारत की

खास बात यह है कि कोविड की त्रास्दी के चलते हालांकि पिछले 9 सालों में जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय दोनों में वृद्धि धीमी रही, लेकिन गरीबी उन्मूलन के प्रयास ज्यादा फलीभूत हुए और गरीबी घटने की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई।

प्रतिव्यक्ति आय में 2003–04 और 2013–14 के दस सालों के दौरान 5. 22 प्रतिशत सालाना वृद्धि हुई। 2013–14 से लेकर 2022–23 के दौरान 9 वर्षों में यह वृद्धि 3.76 प्रतिशत वार्षिक रही। यानि चाहे यूपीए का कालखंड हो या एनडीए का, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि बदस्तूर जारी रही। इससे पहले भी भारत में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती रही है। मसलन, 1950–51 से 1980–81 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 1.37 प्रतिशत वार्षिक रही तो 1980–81 से 1990–91 के दौरान 3.0 प्रतिशत। 1990–91 से 2004–05 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 3.8 प्रतिशत रिकार्ड की गई। आजादी के बाद के कालखंड में हालांकि प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में खासी वृद्धि के बाद भी गरीबी के आपात में कमी तो आती रही लेकिन गरीबी में वह कमी संतोषजनक नहीं रही। इस बीच गरीबी रेखा की परिभाषाएं भी बदलती रही। लेकिन यदि हम देखें तो यदि 2005 में जब हमारी जनसंख्या मात्र 115.46 करोड़ थी, 64.5 करोड़ लोगों (जनसंख्या का 56.4 प्रतिशत) का बहुआयामी गरीबी से पीड़ित होना बताता है कि लगातार ग्रोथ के बावजूद हम गरीबी पर संतोषजनक तरीके से विजय नहीं पा सके। इस बारे में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ग्रोथ के पहले चरण में आय और संपत्ति की असमानतायें भी बढ़ी, जिसके कारण गरीबी दूर करने में कम सफलता हासिल हो सकी। लेकिन यूएनडीपी के आंकड़े दिखाते हैं कि वर्ष 2005–06 से 2015–16 के दौरान, 10 सालों में गरीबों की संख्या 64.5 करोड़ से घटकर 37 करोड़ तक पहुंची और भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्ष 2005–06 में 0.283 से घटकर 2015–16 में 0.122 तक पहुंचा। लेकिन 2019–21 में यानि मात्र 4–5 सालों में जिसमें करीब एक साल से ज़्यादा कोरोना काल भी था, यह सूचकांक मात्र 0.069 पर आ गया और गरीबों की कुल संख्या इन मात्र 5 सालों में घटकर 23 करोड़ तक पहुंच गई है यानि मात्र 5 सालों में लगभग 38 प्रतिशत की कमी। लेकिन इससे पहले के 10 सालों में यह कमी 42.6 प्रतिशत की थी।

यहां खास बात यह है कि कोविड की त्रासदी के चलते हालांकि पिछले 9 सालों में जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय दोनों में वृद्धि धीमी रही, लेकिन गरीबी उन्मूलन के प्रयास ज्यादा फलीभूत हुए और गरीबी घटने की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ गरीबी को घटाने में कम भूमिका निर्वहन करती है और समावेशी नीतियां गरीबी पर ज्यादा गहरी चोट करती है।

यानि देखा जाए तो बाद के 5

सालों में गरीबी घटने की रफ्तार में वृद्धि तो हुई ही है, आज भारत सिर उठा करके कह सकता है कि अब हम दुनिया में गरीबी को कम करने में महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

क्या होती है बहुआयामी गरीबी

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनडीपी द्वारा गरीबी की एक परिभाषा का इस्तेमाल होता है, जिसे बहुआयामी गरीबी कहते हैं। यह परिभाषा सभी देशों के लिए एक समान होती है। दुनिया में अलग–अलग देशों की सरकारों द्वारा गरीबी की अलग–अलग परिभाषाओं का उपयोग करने के कारण, एक ओर तो गरीबी का एक जैसा आकलन संभव नहीं हो पाता और इस कारण दुनिया के विभिन्न मुल्कों के बीच तुलना करना भी कठिन हो जाता है।

गरीबी रेखा की सरकारी परिभाषा हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है और अक्सर उसकी आलोचना भी होती रही है। ग़ौरतलब है कि यूपीए शासन के दौरान, जब उस समय के योजना आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रूपए प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 26 रूपए प्रतिदिन की गरीबी रेखा बताई गई तो उसकी खासी आलोचना भी हुई थी। इसलिए चाहे सरकार द्वारा घोषित गरीबी रेखा हो या वैश्विक स्तर पर कोई एक राशि (जो यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त क्रय शक्ति समता आधार पर 2. 15 डालर है), वास्तविक गरीबी को शायद पूरी तरह से परिलक्षित नहीं कर पाती। इसीलिए यूएनडीपी की बहुआयामी गरीबी की परिभाषा सही मायने में गरीबी को बेहतर तरीके से दिखाने का काम करती है। ऐसे में जब यूएनडीपी यह निष्कर्ष निकालती है कि शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, मकान और परिसंपत्तियां सबको समाहित करती हुई बहुआयामी गरीबी भारत में घटी है, तो इस बावत राजनीतिक या आंकड़ों से हेराफेरी का कोई आरोप लगाना संभव नहीं है।

गरीबी से मुक्ति का भारतीय फार्मूला

रिपोर्ट के विस्तार में जाने पर पता चलता है कि इस बहुआयामी गरीबी के विभिन्न आयामों में भारत का कार्य निष्पादन न केवल अन्य देशों से बेहतर रहा, बल्कि पिछले 10 वर्षों की तुलना में अंतिम 5 वर्षों में और भी बेहतर रहा, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक घटने की दर कहीं ज्यादा तीव्र थी, यानि 10 प्रतिशत वार्षिक। यूपीए के दस सालों में यह गति 6.6 प्रतिशत वार्षिक ही थी।

नरेंद्र मोदी सरकार का बहुआयामी गरीबी के निर्धारकों पर विशेष ध्यान रहा। आज भारत में बाल मृत्यु दर घटकर मात्र 1.5 प्रतिशत रह गई है, जो 2015–16 में 2.2 प्रतिशत थी। 2005–06 में यह 4.5 प्रतिशत थी। यह भारतीय बच्चों के पहले से बेहतर स्वास्थ्य का जीता जागता सबूत है। पोषण और कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में भी भारी सुधार हुआ है, जो 2005–06 में 44.3 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 21.1 प्रतिशत और 2019–21 में केवल 11.8 प्रतिशत रह गया है। आवास की बात करें तो पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर लगभग 3 करोड़ घर बनाए गए हैं, जिस पर केंद्र द्वारा 5 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। कोरोना के कारण सबके लिए पक्के आवास का लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब तक मुश्किल से कुछ लाख लोग ही बचे हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है। यूएनडीपी के अनुसार, वर्ष 2015–16 में कुल 23.5 प्रतिशत आबादी पक्के और आरामदायक घरों से वंचित थी और 2019–21 में केवल 13.6 प्रतिशत।

नरेंद्र मोदी सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल (सभी घरों तक पाइप से पानी) पर तेजी से काम हुआ है और अब यूएनडीपी के अनुसार 2019–21 में केवल 2.7 प्रतिशत आबादी सुरक्षित पेयजल से वंचित थी। स्वच्छता की बात करें तो पिछले 8 वर्षों में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मार्च 2023 तक गरीब महिलाओं को 9.50 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और मार्च 2023 तक देश में कुल 31.26 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे। ऐसा माना जाता है कि हमारी आबादी का बहुत कम प्रतिशत बचा है जिसके पास एलपीजी गैस कनेक्शन के रूप में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच नहीं है। आज देश के दूर–दराज के गांवों तक भी बिजली पहुंच चुकी है और सरकार का दावा है कि देश के 100 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

ये दुनिया के लिए एक सबक है। बहुआयामी गरीबी को भी दूर किया जा सकता है, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और आवश्यक प्रयासों की जरूरत है।

केन्द्र की मोदी सरकार पर अक्सर विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगता रहा है कि यह गरीबों पर कम और अमीरों पर ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित आंकड़े इस आरोप को सिरे से खारिज करते दिखाई दे रहे हैं। इस बात से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि सरकार आवास, पेयजल, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना आदि के लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करे और गरीब जनता अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से मुक्त होकर देश के विकास में जुट जाए और आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होते–होते हमारा देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो। ❑❑

हमारी चाल तो ठीक, पर मंजिल बहुत दूर

यह महज इत्तेफाक नहीं है कि कई अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां लगातार विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बारे में नकारात्मक और पांचवीं अर्थव्यवस्था भारत के बारे में एक ही समय में सकारात्मक राय व्यक्त कर रही है। हालांकि इन रेटिंग्स से वैश्विक अर्थतंत्र में तत्काल कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला, परंतु इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में अवश्य बढोतरी होने वाली है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहने वाला है। फिंच, एसएंडपी और मार्गन स्टेनली, सब ने चीन और अमेरिका दोनों देशों और उनकी बड़ी कंपनियों की डाउनग्रेडिंग की है, जबकि भारत की विकास दर को अपग्रेड किया है। पर भारत के लिए यह समय खुश होकर बैठने का नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार के इस सकारात्मक संदेश के हिसाब से बड़ी पूंजी को अवशोषित करने की क्षमता विकसित करना चाहिए।

चीन में इस समय जो आकड़े आ रहे हैं, वे इस बात का संकेत करते हैं कि वहां इस समय उदासीनता का माहौल है। कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। सभी प्रमुख सेक्टर में मंदी के कारण लगता है कि चीन को फिर से एक बड़े बेलआउट पैकेज की घोषणा करनी पड़ सकती है, क्योंकि निर्यात सिकुड़ने के साथ साथ घरेलू मांग में भी कोई उठाव नहीं है। जून 2023 में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 12. 4 फीसदी की गिरावट आई है। इस समय चीनी उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास टूटा पड़ा है। प्रोपर्टी मार्केट अब भी औंधे मुंह पड़ा हुआ है, जो कि चीन की जीडीपी में एक तिहाई वजन रखता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जून में समाप्त तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले केवल 0.5 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी देखी गई है। खुदरा बाजार और निवेश में भी नमी है।

एक अगस्त को जारी अपनी रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी फिंच ने कहा है कि यदि चीनी बैंक कम ब्याज दर पर होम लोन को रिफायनेंस करना जारी रखते हैं तो उनकी लाभदायकता में 1 से 5 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। ऐसा होना लाजिमी भी है, क्योंकि चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेस के जरिए सभी बैंकों से कहा भी

सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का आकलन है कि भारत की जीडीपी में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से लेकर 6.9 प्रतिशत तक रहने वाला है। यानी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है।

– विक्रम उपाध्याय

है कि वे मॉरगेज लोन की ब्याज दर कम ही रखें और पुराने लोन की जगह नये लोन जारी रखे। फिंच का कहना है कि यदि ऐसा बड़े पैमाने पर होता है तो इसका सीधा असर चीन के बैंकों की लाभप्रदता पर होगा, क्योंकि चीन के बैंकों के कुल लोन का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मॉरगेज लोन ही है। फिंच ने ही 3 अगस्त एक और अपनी रिपोर्ट में चाइना ग्रेटवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रेटिंग्स 'ए' से घटाकर 'ए माइनस' कर दिया। फिंच का कहना है कि शी जिनपिंग की सरकार द्वारा यदि चाइना ग्रेट वाल को आर्थिक मदद मिलना जारी नहीं रहता तो यह बैंक डिफॉल्ट भी हो सकता है। चाइना ग्रेटवाल अभी तक सरकार का प्रौक्सी बैंक बन कर ही काम कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने अपनी सपोर्ट कम कर दी है। शायद यही कारण है कि इस बैंकिग संस्थान ने अभी तक अपने वित्तीय परिणाम जारी नहीं किए हैं, जबकि 30 अप्रैल तक इसे जारी हो जाना चाहिए था। फिंच का आकलन है कि वित्तीय परिणामों को जारी होने में देरी से इसके वित्तीय स्रोतों में भी कमी आएगी और साथ में यह बात भी सच साबित होगी कि इस बैंकिंग संस्थान पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि चाइना ग्रेटवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में चीनी वित्तमंत्रालय की सीधी 73. 5 प्रतिशत हिस्सेदारी है और बाकी हिस्सेदारी भी चीन के अन्य सरकारी विभागों की है।

अंतरराष्ट्रीय निवेश सलाहकार मार्गन स्टेनली ने भी चीन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अपने निवेशकों को कहा है कि यह समय बीजिंग में निवेश करने का नहीं है, क्योंकि वहां बाजार में कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर स्टैंडर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) ने भी निराशा ही जताई है। एसएंडपी का भी कहना है कि चीन की जीडीपी वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत ही रहने वाला है। गोल्डमैन साच्स ने भी चीन की विकास दर का आकलन घटा दिया है। पहले इस एजेंसी ने चीन की विकास दर 6 प्रतिशत रहने का आकलन किया था, पर अब इसे घटाकर 5.4 प्रतिशत का आकलन किया है। अब खुद चीन भी मान रहा है कि उसकी बस अब छूट रही है। 4 अगस्त को चीन की सरकार ने एक बार फिर लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए एक साथ कई उपायों की घोषणा की। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि शुक्रवार को कई सरकारी एजेंसियों और सेंट्रल बैंक ने यह संकल्प लिया कि 2023 की दूसरी छमाही में आर्थिक प्रगति दुबारा वापस लाने के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय और आर्थिक पैकेज पर लगातार काम करेंगे। चीन मैक्रो लेवल पर नीतियों को लागू करेगा, निवेशकों का विश्वास बहाल करेगा और घरेलू बाजार में मांग बढ़ाने पर काम करेगा। लेकिन अमेरिका यूरोप, आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के साथ कई तरह के विवाद के बाद भी बीजिंग पुरानी लय प्राप्त कर सकेगा, इसमें सभी को संशय है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को लेकर भी तमाम आशंकाएं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने जताई है। अमेरिकी बाजार में तब हाहाकार मच गया, जब फिंच ने अमेरिका की रेटिंग 'एएए' से घटाकर 'एए प्लस'' कर दिया। अमेरिकी शेयर बाजार में 2 अगस्त को फिंच की रिपोर्ट आने के बाद जबर्दस्त बिकवाली चली और एसएंडपी 500 इंडेक्स में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई। फिंच की इस रिपोर्ट से पूरा अमेरिकी प्रशासन बौखला गया और सभी प्रमुख अधिकारी फिंच की रिपोर्ट को बकवास करार देने में लग गए। फिंच का आकलन है कि अमेरिका का अगले तीन साल में और कर्ज बढ़ जाएगा और बैंकिंग सेक्टर पर इसका जबर्दस्त नकारात्मक प्रभाव होगा। अभी कुछ ही माह पहले अमेरिका पर डिफाल्ट का खतरा आ गया था। अमेरिका की समस्या उसके कर्ज की बढ़ती सीमा से है। 2011 तक अमेरिका का जीडीपी डेब्ट रेशियो 65.5 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है और अगले तीन साल में इसके 115 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। अमेरिकी प्रशासन इस समय राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। फिंच का कहना है कि पिछले 20 साल से अमेरिका राजनीतिक हाराकिरी का शिकार हो रहा है।

भारत के लिए फिलहाल अच्छी अच्छी खबरें हैं। सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट का अपना ही अनुमान बढ़ा दिया है। सभी का आकलन है कि भारत की जीडीपी में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से लेकर 6.9 प्रतिशत तक रहने वाला है। यानी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। हमारी चाल तो ठीक है पर मंजिल बहुत दूर है। हम अभी भी अमेरिका और चीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। अमेरिका और चीन हमसे पांच गुणा बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। विश्व व्यापार में चीन की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तो अमेरिका की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। वहीं भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम है। पर अच्छी बात है कि भारत के प्रति पूरी दुनिया में विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन कर उभरे हैं। मार्गन स्टेनली जो कि दुनिया भर में 6 ट्रिलियन डॉलर के निवेश को सलाह देती है, भारत के शेयर बाजार को वेटेज वाला बाजार हाल ही में घोषित किया है। उसी ने कहा है कि भारत अब 2013 वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, तब उसे 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में से एक बताया गया था। तब देखना है कि 2023 से आगे भारत कहां जाता है।❑❑

पढ़े-लिखे लोगों में बढ़ रही है पलायन की प्रवृत्ति

लोकसभा से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जानकारी दी है कि रोजी रोजगार और बेहतर जीवन जीने की लालसा में प्रतिदिन औसतन 440 भारतीय नागरिकता छोड़ पराए मुल्क को जा रहे हैं। एक सवाल के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि पिछले साढे तीन सालों में 5 लाख 61 हजार 272 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। देश छोड़कर जाने वाले यह भारतीय नागरिक 135 देशों में गए हैं जिनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान भी शामिल है।

विदेश मंत्री ने बताया है कि 2020 में 85256 भारतीय नागरिकों ने, 2021 में 163370 नागरिकों ने, 2022 में 225620 नागरिकों ने और 2023 में 30 जून तक 87026 नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है।

जनसंख्या के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है ऐसे में माना जा रहा है कि इसे जनसांख्यिकीय लाभांश दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होगा इसी के मद्देनजर सरकार ने कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम चलाएं हैं और अपने रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने प्रवासी नेटवर्क से जुड़ने और राष्ट्रीय लाभ के लिए इसकी प्रतिष्ठा का उपयोग करने का जिक्र करते हुए कहा है कि विदेश में भारतीय समुदाय राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराय और कोपनहेगन कंसेशंस के अध्यक्ष ब्योन लोमबोर्ग ने पलायन को लेकर हुए हाल के अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर पूरी दुनिया को माइग्रेशन के लिए खोल दिया जाए तो ग्लोबल जीडीपी में डेढ़ सौ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह सही भी लगता है क्योंकि गरीब देशों में डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर या किसी भी क्षेत्र के कौशल प्राप्त दक्ष कामगार साल भर में जितनी आय अर्जित करते हैं अगर भी अमीर देशों में चले जाते हैं तो उनकी आय में कई गुना की वृद्धि हो जाती है। लेकिन पेंच यह है कि पलायन कर जो लोग अमीर देशों की ओर जाते हैं वह कमाई करने के साथ ही वहां की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। कारोबार नौकरी और पढ़ाई के लिए विदेश जाकर वहां की नागरिकता लेने पर भारतीय

विदेश मंत्री ने बताया है कि 2020 में 85256 भारतीय नागरिकों ने, 2021 में 163370 नागरिकों ने, 2022 में 225620 नागरिकों ने और 2023 में 30 जून तक 87026 नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है।

–अनिल तिवारी

नागरिकता स्वतह रद्द हो जाती है। बीते 10 सालों में अमेरिका की नागरिकता लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक 'भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते।' अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहते हुए दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो अधिनियम की धारा 9 के तहत उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है।

भारत की नागरिकता छोड़ने के पीछे प्रमुख तीन कारण पढ़ाई, नौकरी और कारोबार सामने आया है। इसके अलावा कुछ हद तक रहन–सहन के स्तर को लेकर भी लोगों ने विदेश में रहने के लिए नागरिकता हासिल की है। अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ओर रुख करने की वजह अधिकाधिक वैभवपूर्ण रहन सहन भी है।जहां तक पढ़ाई का सवाल है साल 2020 के मुकाबले 2021 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 10 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई, वहीं 2021 की तुलना में 2022 में अमेरिका जाने वालों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों में से 60 प्रतिशत से अधिक युवा देश में वापसी नहीं करते।

व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए जब किसी देश का नागरिक अपना देश छोड़ दूसरे देशों में बसने लगता है तो निश्चित रूप से यह स्थिति उस देश के लिए चिंता की विषय हो जाता है। खासकर मेडिकल की पढ़ाई के बाद डॉक्टरों के पलायन को लेकर कुछ समय पहले तक भारत में युवाओं को भावनात्मक रूप से प्रेरित करने का प्रयास किया जाता रहा कि जिस देश में उनकी पढ़ाई लिखाई पर ढेर सारा मद खर्च किया है जब सेवा देने का

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक 'भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते।' अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहते हुए दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो अधिनियम की धारा 9 के तहत उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है।

समय आता है तो युवा देश को छोड़कर अपनी प्रतिभा का योगदान किसी और देश में देने लगे यह नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। मगर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा प्रतिभा पलायन रफ्तार के साथ बढ़ता गया। अब तो स्थिति यह है कि जिनके भारत में जमे जमाए कारोबार हैं उनमें भी नागरिकता त्याग कर दूसरे देशों में जाकर रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। कुछ समय पहले आई फैमिली ग्लोबल सिटीजंस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 8000 अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ने की तैयारी में है। भारत में हर साल लाखों युवा इंजीनियरिंग चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में तकनीकी तालीम हासिल करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं, मगर उनमें लगभग 45 प्रतिशत को उनकी इच्छा और क्षमता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता ऐसे में वे दूसरे देशों का रुख करते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में वेतन भत्ते और काम करने की स्थितियां बहुत खराब है इसलिए भी मौका मिलते ही युवा निकल लेते हैं और यहां की नागरिकता छोड़ देते हैं। बेहतर कारोबारी माहौल ना होने अथवा व्यवसायियों में असुरक्षा बोध के चलते भी पलायन का ट्रेंड दर्ज किया गया है।

मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे सैकड़ों कार्यक्रमों के जरिए विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। व्यवसाय के लिए अनेक आर्थिक सुविधाएं दी जा रही है, इसके बावजूद अगर हर साल नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़कर ही सामने आ रही है तो निश्चित रूप से इसके कारणों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। रोजगार के अवसर केवल कौशल विकास से नहीं सृजित होते हैं, इसमें श्रम शक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने वालों के समर्पण और प्रतिभा की भी जरूरत होती है। भारत अपनी विविधता के साथ प्राचीन काल से आत्मनिर्भरता के लिए दुनिया में पहचाना जाता रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के पहले भारत के गांव गणराज्य हुआ करते थे। भारत के गांव इतने समृद्ध थे कि अपनी जरूरत की हर चीज का उत्पादन खुद कर लेते थे। किसी अनमोल चीज के लिए भी नदी पार करना और पार जाकर प्राप्त करना निषिद्ध माना जाता था। बाद के दिनों में जो लोग रोजी रोटी के लिए दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जाते थे उन्हें गांव लौटने पर गांव वाले पूरबिया या परदेसी कह कर संबोधित करते थे। यह ठीक है कि बदलते समय के साथ विज्ञान में प्रगति की है। विकसित तकनीक का लाभ सभी को उठाना भी चाहिए, लेकिन पलायन की कीमत पर शायद नहीं। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री की गारंटी को ख्याल करते हुए सरकार को बढ़ रहे पलायन पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर आर्थिक नीतियों के साथ आगे आना चाहिए। वरना जिस तरह भारत के कभी समृद्ध रहे गांवों में पलायन के कारण अब कुछ न कर सकने वाली जनसंख्या ही बची है, ठीक उसी तरह तेज गति से हो रहे ब्रेन ड्रेन के कारण भारत में भारतीय प्रतिभा, मेधा का अभाव होने की संभावना बढ़ने लगेगी। ❑❑

अर्थव्यवस्था में छलांग

विनिर्माण से बनेगा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

वर्ष 2014 में दुनिया के पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर थी, सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए अब भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहरा चुके हैं। एसबीआई अनुसंधान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में में हर दो साल में 0.75 ट्रिलियन डॉलर जुड़ने की संभावना है। मार्च 2023 तक भारत की वास्तविक जीडीपी के अनमानो को देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि वर्ष 2047तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 20 लाख डॉलर तक पहुंच सकता है। 2027 तक जीडीपी में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 4 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसके लिए भारत को रुपए के संदर्भ में लगभग 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की जरूरत है। फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 6.5 से लेकर 7 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि के साथ यह लक्षय निश्चित रुप से संभव है।

हालांकि कोविड महामारी के कारण उपजी प्रतिकूलताओं के चलते सापेक्ष सफलता के बावजूद वर्ष 2004 से 2014 की अवधि की तुलना में वर्ष 2014 से 2023 के बीच भारत के विकास की गति धीमी रही है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है की रैंक 10 से रैंक 5 तक की यात्रा अपेक्षाकृत आसान थी, क्योंकि इन रैंकों को रखने वाले देशों की जीडीपी भारत के जीडीपी के आसपास थी। अब तीसरे रैंक और उसके पहले के दो रैको के बीच अंतर बहुत अधिक है। वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी चीन की जीडीपी का पांचवा हिस्सा और अमेरिका का छठवां हिस्सा से भी थोड़ा कम होगी। वर्तमान में चीन की जीडीपी 20 ट्रीलियन डॉलर और अमेरिका की 26 ट्रिलियन डॉलर है। कहा जाता है कि आर्थिक विकास की उच्च दर और परिणामी आर्थिक आकार बेहतर चीजों के अवसर प्रदान करते हैं। यह सच है कि 1980 के दशक के बाद से 4 दशकों की तेज वृद्धि के परिणाम ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और सरकार घरेलू बाजार के आकार को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लायक बनाया है।

सरकार अगर सही नीतिगत ढांचा अपनाती है तो इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत में इसके लिए आवश्यक दक्षता और कार्य कुशलता भी है।

– के.के. श्रीवास्तव

अनुचित राजकोषीय नीति से बचते हुए तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता से समझौता किए बिना आर्थिक विकास की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की सराहना की जानी चाहिए। इन नीतियों ने भारत की विकास गाथा के लिए स्थायीत्व के आयाम सुनिश्चित किए हैं। बावजूद हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यदि उचित सुधार पेश किए जाएं तो भारत की संभावित वास्तविक जीडीपी दर प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ सकती है अगर ऐसा होता है तो एक दशक के भीतर हमारी अर्थव्यवस्था का आकार अपने आप दुगना हो जाएगा। चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से पहले से ही पांच गुनी बड़ी है ऐसे में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत से कम की टिकाऊ आर्थिक वृद्धि दर के लिए किसी भी मोर्चे पर समझौता करने से भारत के समक्ष मुंह बाए खड़ी रोजगार की गंभीर चुनौती को हल करने में कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर भारत क्षमता को वास्तव में बदलना चाहता है तो 8 प्रतिशत वार्षिक विधि दर को आगे रखकर नीतियां बनानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम छलांग लगाकर आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो इसका रास्ता क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ाने से सहज ही प्राप्त होता है।

कहा जाता है कि हार्ड पावर के बिना सॉफ्ट पावर अच्छा नहीं होता। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के मुताबिक हार्ड पावर का मतलब औद्योगिक और तकनीकी ताकत है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी अब भी 15 प्रतिशत बनी हुई है। लेकिन पिछले दो दशकों में मुख्य रूप से चीन से होने वाले आयात के कारण भारत एक तरह से वि–औद्योगीकरण की राह पर चल पड़ा है। हम अपनी विनिर्माण क्षमता को साकार करने में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे शासकों में दक्षता से अधिक समानता को प्राथमिकता देने का निर्णय कर लिया है। हमारी नीतियों के ठीक विपरीत चीन ने दक्षता हासिल करने का जुनून दिखाया है। 1948 में ही भारतीय संसद ने श्रम के पक्ष में श्रम कानून पारित किए थे। स्मरण रहे कि तब पश्चिम के देशों में भी इस तरह के कानून मौजूद नहीं थे।

वर्ष 1950 के दशक के उत्तरार्ध से वित्तीय क्षेत्र को इक्विटी विचारों द्वारा शासित करने की मांग की गई थी। 2011 आते–आते सरकार ने भूमि अधिग्रहण बेहद मंहगा कर दिया। इस प्रकार उत्पादन के सभी तीन प्रमुख कारक भूमि, श्रम और पूंजी भारत में महंगे हो गए और उन तक पहुंच कठिन हो गई। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हुए इन कठिनाइयों के साथ अत्यधिक भ्रष्ट और फालतू के नियम से बंधे निचले स्तर की नौकरशाही द्वारा नियंत्रित एक घुटन भरी नियामक व्यवस्था की बेड़ियां विकास के लिए बाधा बन गई।

आजादी के बाद से कई दशकों तक ऐसे राजनीतिक दल थे जो निर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक निवेशकों से अपने लिए कुछ अतिरिक्त पाउंड की आशा रखते थे।

केंद्र की वर्तमान सरकार ने इन मुद्दों को हल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। फालतू के नियमों के अनुपालन का बोझ कम कर दिया है। बाजार के लिए पूंजी को सस्ता कर दिया है। सरकार ने श्रम संगठन के माध्यम से श्रम बाजार को भी ढ़ीला करने का प्रयास किया है लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों ने बाधा उत्पन्न की है तथा नियमों को लागू करने में हीला–हवाली भी की है। श्रम राज्य का विषय है। केंद्र सरकार की कोशिशों के बावजूद भी भूमि अधिग्रहण अभी बहुत महंगा सौदा बना हुआ है। आखिर बिना जमीन के कोई भी विनिर्माण इकाई कैसे स्थापित हो सकती है।

कुल मिलाकर भारत में विनिर्माण उन अधिकांश देशों की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक महंगा है जो निवेश आकर्षित करने के लिए भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसीलिए भारत में बनाने की तुलना में आयात कर लेना सस्ता है। देश के भीतर नियमों की अनदेखी के कारण भारत ने विदेशों में अधिक कुशल उत्पादकों के साथ विदेशी व्यापार समझौता किया। इससे आयात और सेकेंडरी असेंबली सस्ती हो गई। इस नीति के चलते 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी धक्का पहुंचा है। व्यापार व्यवस्था के असंगत होने के कारण ही पूर्व में पश्चिमी विनिर्माण चीन के तरफ झुक गया था। ऐसे में अगर हम सात आठ प्रतिशत की दर से बढ़ना चाहते हैं तो एक क्षेत्र के रूप में विनिर्माण क्षेत्र में छलांग लगाने की जरूरत है। अनुभव यह भी बताता है कि हमेशा कुछ प्रमुख खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो व्यापक क्षेत्र में रास्ता तैयार करते हैं। भारत को इस प्रतियोगिता से आगे बढ़कर सोचना होगा।

1980 के दशक में भारत में आर्थिक विकास दर बढ़कर लगभग 5.5 प्रतिशत हो गयी थी, जो 1970 के संकटग्रस्त दशक में मात्र 2.5 प्रतिशत पर थी। यही वह दौर था जब भारत में मध्यवर्ग का जन्म हुआ। इससे विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तु, उपयोगी सामग्री और टिकाऊ वस्तुओं की मांग पैदा हुई। लाभार्थी ऑटोमोबाइल उद्योग था, क्योंकि तब दो पहिया वाहनों और छोटी कारों की बहुत मांग थी। इंजीनियरिंग

(शेष पृष्ठ 17 पर ...)

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ): एक नई पहल

नई शिक्षा नीति के तहत कई बड़ी घोषणाएं की गई थी उन्हीं में से एक घोषणा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की भी थी। एनआरएफ का मूल उद्देश्य अलग–अलग मंत्रालयों के द्वारा स्वतंत्र रूप से दिए गए रिसर्च संबंधी अनुदान को एकत्रित करना एवं शोध कार्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों से जोड़ना है। इसके साथ शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना है ताकि हर क्षेत्र में शोध का महत्व बढ़ाया जा सके। एनआरएफ के जरिए शोधकर्ताओं विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने एनआरएफ के लिए 5 वर्षों में 50000 करोड़ का बजट लागू किया है जिसमें 14000 करोड रुपए का योगदान सरकार करेगी बाकी निजी क्षेत्र से आएगा और इसके लिए निजी भागीदारी को प्रबल तरीके से प्रोत्साहित करना होगा। शोध के मामले में भारत की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और यह बहुत ही आंशिक रूप से अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत में शोध अनुसंधान में निवेश इस समय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7 फीसदी है, वहीं अगर हम इसकी तुलना अन्य राष्ट्रों से करें तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.8 फ़ीसदी और चीन अपनी जीडीपी का 2.1 फ़ीसदी शोध कार्यों में निवेश करता है। यह स्थिति तब है जब भारत की जीडीपी इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में केवल 7.6 और 5.1 गुना छोटी रह गई है। अतः एनआरएफ की कोशिश रहेगी कि भारत में अलग–अलग धाराओं में रिसर्च कर रहे सभी शोधार्थियों को फंड की कमी ना हो।

भारत में प्रति मिलियंन जन संख्या पर 366 अनुसंधान और विकास के कर्मचारी हैं, जबकि चीन में यह संख्या 2366 है। भारत में अनुसंधान गतिविधियों पर खर्च बहुत कम है। भारत इनहाउस और आरएंडडी पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक चौथाई प्रतिशत ही निवेश करता है, जबकि विश्व का औसत निवेश इस क्षेत्र में 1.4 फ़ीसदी है। हालांकि भारत

एनआरएफ को सामान्य सरकारी रवैया, नौकरशाही उदासीनता और कठोरता को छोड़कर सामाजिक रूप से प्रासंगिक और उद्योग पसंदीदा अनुसंधान को जोड़कर सार्थक परिणाम लाने के लिए आगे आना चाहिए।

– डॉ. जया कक्कड़

की जनसंख्या और विकास संबंधी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा है की दुर्लभ संसाधनों की मांग बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 फीस भी खर्च करना पूर्णतया गलत नहीं है। भारत को अनुसंधान एवं विकास पर वर्तमान की तुलना में कम से कम 4 से 5 गुना अधिक संसाधन लगाने की जरूरत है ताकि स्वायत्त सरकारी संस्थानों (जो जीडीपी के 0.4 फ़ीसदी पर अल्प विश्वविद्यालय स्तर के अनुसंधान द्वारा पूरक) पर निर्भर न रहना पड़े। हालांकि एनआरएफ इस दिशा में ज्यादा लाभकारी दिखाई नहीं प्रतीत होता, क्योंकि अनुसंधान के प्रचार प्रसार में भी निवेश को बढ़ाने की जरूरत है।

एनआरएफ में काफी हद तक अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के तत्व है और इसे उसी के अनुरूप तैयार किया गया है। एनआरएफ के प्रस्तावित विधेयक में अन्य देशों की विज्ञान एजेंसियों की कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान प्रयासों की सीमाओं पर आलोचनात्मक रचनात्मकता और नवीनता लाना है। एनआरएफ वैज्ञानिक अनुसंधान को एक उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना चाहता है ताकि शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ स्वायत्त निकायों में भी अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाए। इसका प्रयास यह भी होगा कि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की सहभागिता बढ़ाया जा सके क्योंकि तकनीकी रूप से उन्नत देशों में निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी भूमिका रखते हैं। साइलोस में वैज्ञानिक अनुसंधान कम करने के लिए अनुसंधान निकायों द्वारा किए गए सभी प्रयासों को एकीकृत करने की कोशिश करेगा।

एनआरएफ के प्रस्तावित विधेयक से एक बात तो साफ है कि अब अनुसंधान के कार्य का सरकार पर कम बोझ रहेगा इसलिए वह अन्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकती है।

एनआरएफ के प्रस्तावित विधेयक से एक बात तो साफ है कि अब अनुसंधान के कार्य का सरकार पर कम बोझ रहेगा इसलिए वह अन्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकती है।

निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन अवरोधों की कमी नहीं है। उदाहरण के लिए अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी जो कि 36000 करोड रुपए है, को कैसे जुटाएगी? सरकार दिशा निर्देश कैसे बनाएगी और लागू कैसे करेगी? एनआरएफ की सफलता इस बात से भी तय होगी।

तकनीकी रूप से उन्नत देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया के निजी क्षेत्र ने अनुसंधान और विकास के संचालन और इसके व्यक्त पोषण में अग्रणी भूमिका निभाई है पर भारत में यह आंकड़ा बहुत कम है। भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी केवल 35 प्रतिशत है। इसकी तुलना में इजरायल की 88 प्रतिशत है। भारत में बड़ी कंपनियों के बिक्री बजट का एक प्रतिशत जो कि वास्तव में 0.3 प्रतिशत मात्र है अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। अतः सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए कैसे प्रेरित करेगी।

देखा जाए तो भारत अभी भी अनुसंधान के क्षेत्र में सजग नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2015 में 81 से बढ़कर 2022 में 40 हो गई है इसी तरह प्रकाशनों की संख्या के आधार पर रैंकिंग 2010 और 2020 के बीच सातवें स्थान पर पहुंच गई है। अगर इसकी तुलना अमेरिकी पेंटेटिंग और प्रशासन की गुणवत्ता से करें तो भारत का स्थान बहुत नीचे है। हम शुरुआत से दूसरों से नवाचार खरीदते रहे हैं। यह जानते हुए भी कि हमारे पास निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पंक्ति में सबसे आगे रहने की क्षमता है। हमें यह समझना होगा कि भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए अनुसंधान में पैमाने और गुणवत्ता दोनों की आवश्यकता है।

एनआरएफ निश्चित रूप से एक सकारात्मक और प्रशंसनीय पहल है। बस आवश्यकता है तो इसके सही तरीके से क्रियान्वयन की। केंद्र की मोदी सरकार अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत है। उदाहरण के लिए सरकार ने नीतिगत सहायता प्रदान करने के अलावा पेटेंट जारी करने की प्रक्रिया को भी बहुत सरल बना दिया है। परिणाम स्वरूप 2014 से 2023 के बीच प्रति वर्ष जारी किए गए पेटेंट की संख्या 7 गुना अधिक बढ़ गई है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित ना रहे बल्कि हमारी आवश्यकताओं के लिए भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। आज हमारे पास प्रतिभा के विशाल भंडार और प्रयोगशालाओं से लैस उत्कृष्ट संस्थान है, फिर भी हम वैज्ञानिक अनुसंधान में कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं।

इसलिए एनआरएफ की कोशिश

है कि यह न केवल अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन और वित्तीय सहायता देकर बल्कि इसे सरकार और उद्योग से जोड़कर सार्थक परिणाम दे सके। साथ ही यह दोनों के धन का उपयोग करके भारत को उसकी पूर्ण क्षमता का अनुभव करा सके, जिससे अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भारत के सफलता का मार्ग प्रशस्त हो।

एनआरएफ अनुसंधान एवं विकास करने में आसानी कैसे प्रदान कर सकता है?

1. सरकार के मंत्रालय वर्तमान में संसाधनों के कम आवंटन के साथ व्यक्तिगत प्रयास करते हैं इसलिए वे अपने अनुसंधान को एनआरएफ द्वारा संचालित और प्रबंधित कर सकते हैं।
2. निजी क्षेत्र सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के तहत अनुसंधान प्रयोगशालाओं को प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं के लिए अपने सुविधाएं साझा करना चाहिए ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।
3. परियोजना स्वीकृत होने के बाद बिना अधिक समय अंतराल के अनुसंधान के अनुदान का वितरण जल्द से जल्द होना चाहिए।
4. कर प्रोत्साहन प्रदान करके निजी योगदानकर्ताओं में उनके हिस्से के निवेश को प्रेरित किया जाना चाहिए।
5. शोधकर्ताओं को किसी भी तरह की कागजी कार्यवाही या अन्य प्रकार के बोझ से मुक्त करना चाहिए ताकि उन्हें धनराशि शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध हो सके।
6. वैज्ञानिकों को आवंटन के अनुसार धन के उचित उपयोग के लिए जवाब देह बनाया जाना चाहिए और धन खर्च में लचीलापन होना चाहिए और इसके लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएसआर) के बजाय स्वतंत्र दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए।
7. वर्तमान में अनुसंधान निधि बहुत ही असमान रूप से वितरित की जाती है जिससे विज्ञान के अधिकांश शोधछात्रों को अनुसंधान के लिए बहुत कम या कोई अनुभव नहीं मिल पाता। अतः एनआरएफ का लक्ष्य धन के वितरण को लोकतांत्रिक बनाना है ताकि बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक पूरी योजना से लाभान्वित हो सके।

अतः एनआरएफ को सामान्य सरकारी रवैया, नौकरशाही उदासीनता और कठोरता को छोड़कर सामाजिक रूप से प्रासंगिक और उद्योग पसंदीदा अनुसंधान को जोड़कर सार्थक परिणाम लाने के लिए आगे आना चाहिए। ❑❑

(पृष्ठ 14 से जारी ...)

विनिर्माण से बनेगा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

कार्यबल सहित इन्फोटेक के क्षेत्र में बूम देखा गया था। दूसरी ओर पेटेंट व्यवस्था में अनुकूल बदलाव तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों के कारण फार्मा उद्योग, सस्ते जेनेरिक की पेशकश करके अमेरिकी बाजार में गहराई तक प्रवेश कर गया। ऑटोमोबाइल, फार्मा और इन्फोटेक ने मिलकर निर्यात को बढ़ावा दिया। विमानन, वित्त, बैंकिंग जैसे सहायक उद्योगों का समर्थन मिला।

लेकिन समय के साथ इन क्षेत्रों ने विभिन्न कारणों से अपनी गति खो दी।खराब उद्योग प्रथाओं और नियामक विफलताओं के कारण फार्मा उद्योग को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इन्फोटेक अब एक परिपक्व क्षेत्र बन गया है। कोविड महामारी के कारण उपभोक्ता मांग स्थिर हो गई है। पिछले दशक में माल निर्यात का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिनिधियों की तुलना में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण आधार की कमी है।

निश्चित रूप से सरकार ने विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। माना जाता है कि प्रारंभिक मेक इन इंडिया अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही है। अब सरकार ने ट्रैक बदलने का फैसला किया है। उसने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर विशेष जोर देने के साथ निवेश और उत्पादन दोनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही भौतिक बुनियादी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश द्वारा विकास इंजन को चालू रखा गया है जिसने बदले में, धातु, सीमेंट जैसे सहयोगी उद्योगों में बड़े निजी निवेश को बढ़ावा दिया है। अंतत धीमी विश्व अर्थव्यवस्था में भारत आसानी से विदेशी पूंजी के प्रवाह की उम्मीद कर सकता है। सरकार अगर सही नीतिगत ढांचा अपनाती है तो इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत में इसके लिए आवश्यक दक्षता और कार्य कुशलता भी है। ❑❑

स्वदेशी सार्वजनिक नीति अनुसंधान का उन्मुखीकरण

देश में इन दिनों सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठनों की बाढ़ आई हुई है। इनमें से ढेर सारे संगठन नीति निर्माण के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। खुद के द्वारा घोषित मिशन और विजन से परे हटकर सरकार को तो गुमराह कर ही रहे हैं, राष्ट्रवादी हितधारकों का धन, संस्कृति, परंपरा तहस–नहस करने के साथ–साथ हमारी युवा पीढ़ी को लूटने पर भी आमादा है। नीति निर्माताओं द्वारा ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू किए जाने के बाद इनकी कलई खुल कर सामने आ गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की देखरेख में चल रही प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक नीति लाबी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुखद है कि स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रवादी हितधारकों के लिए 'स्वदेशी शोध संस्थान' की अनूठी पहल कर सार्वजनिक नीति अनुसंधान क्षेत्र की खाई को पाटने तथा इस क्षेत्र में शुचिता कायम करने का बीड़ा उठाया है।

मालूम हो कि सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठन सार्वजनिक नीतियों की निर्माण प्रक्रिया, प्रारूपण और स्वीकृति को प्रभावित करने में एक आवश्यक घटक है। ऐसे संगठन सरकार द्वारा स्वामित्व और वित्त पोषित हैं या गैर सरकारी संगठनों के स्वामित्व में है या किसी अन्य प्रकार के स्वामित्व और वित्त पोषण में चल रहे हैं। अपने खुद के मिशन और विजन की विशेषता के साथ ऐसे संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रक्षा, दूरसंचार, नीति, आदि क्षेत्रों में समग्रता के साथ काम करने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश संगठनों का कार्य उनके प्रोफाइल कथन के विपरीत होता है। आमतौर पर ऐसे संगठन अपनी प्रकृति में अकादमी होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे अकादमिक पाठ्यक्रम भी चलाते हों। हालांकि ऐसे संगठनों में काम करने वालों को शोधकर्ता के रूप में ही नामित किया जाता है। आज ढेर सारे कॉर्पोरेट निकायों द्वारा ऐसे संगठनों को वित्त पोषित किया जाता है। कारपोरेट के अपने हित होते हैं। इसलिए ऐसे संगठनों को वित्त मुहैया कराने वाले तथा

स्वदेशी जागरण मंच का स्पष्ट मानना है भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराएं और सबसे बढ़कर भारतीय युवा शक्ति भारत की ताकत है। इनके लूट की खुली छूट नहीं दी जा सकती।

–आलोक सिंह

संगठनों मे रहकर काम करने वालों के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव उत्पन्न होने की भी बातें उभर कर आती रही हैं। चूंकि वित्तदाताओं की अनदेखी कर ऐसे संगठन अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसका फायदा उठाते हुए शोधकर्ताओं से मनमाफिक रिपोर्ट तैयार कराई जाती है। शोधकर्ता आंकड़ों में हेर फेर कर ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो उनके वित्तीय प्रायोजक के व्यवसाय का पक्ष लेता हो। केवल मुनाफे के व्यवसाय में लगे व्यवसायी ऐसी रिपोर्टों को आधार बनाकर सरकार के निर्णय संबंधी प्रक्रिया पर भी प्रभाव डालते हैं। दरअसल जोड़–तोड़ का यह एक व्यापारिक चक्र है, और ऐसे सार्वजनिक नीति संगठन जनता के खुले दुश्मन है। अनुसंधान संगठनों की उत्तरजीविता निजी वित्त पोषको पर निर्भर है।

आज की कारोबारी दुनिया में व्यवसायिक हित धारक बदल गए हैं। पूर्व में उत्पादों या सेवाओं को सर्वप्रथम विकसित किया जाता था और फिर बाजार से खरीदा जाता था। किसी उत्पाद की सफलता या असफलता बाजार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती थी। बाद में कंपनियों ने बाजार से उस उत्पाद या सेवा के बारे में फीडबैक लेना शुरू कर दिया। यानी व्यवसायी उसी उत्पाद को प्राथमिकता देने लगे जिसे ग्राहकों ने अपनी पूर्व स्वीकृति दी। इस क्रम में समय–समय पर समाज और पर्यावरण की चिंता करने वाले, न्यायपालिका, मीडिया, मशहूर हस्तियों द्वारा उत्पादों का विज्ञापन, आदि ग्राहकों का मनोविज्ञान सेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आज का व्यवसाय मालिकों, प्रबंधको, कार्यकर्ताओं, न्यायपालिका, मीडिया, राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठनों से प्रभावित होता है। कुछ निष्पक्ष अनुसंधान संगठन भी है जो सरकारी

कई एक सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठनों द्वारा हेरफेर कर तैयार की गई सिफारिशों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी हितधारकों द्वारा वित्त पोषित संगठनों की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी शोध संस्थान की पहल की गयी है।

परामर्श पर निर्भर हैं लेकिन अधिकांश संगठन अनुचित प्रस्तुतियों का सहारा लेकर हितधारकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।जो लोग सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठनों को वित्त पोषित करते हैं वह उम्मीद रखते हैं कि उनके हितों की तर्कसंगत ढंग से रक्षा की जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे हितधारक हैं जो बड़े कारपोरेट के पक्ष में या विदेशी कंपनियों के पक्ष में लिए जाने वाले निर्णयों के शिकार हैं।

सार्वजनिक नीति ऐसी होनी चाहिए जो सभी हितधारको पर समानता का प्रभाव डालती हो। सभी द्वारा सम्मान रूप से समझी और व्याख्यायित की जा सके। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अथवा रियल एस्टेट अधिनियम 2016 सभी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में है, जबकि दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 तथा वस्तु एवं सेवा कर आज भी ग्रे एरिया में है और इसीलिए इनका लगातार मूल्यांकन और इनमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

कानून में प्रत्येक उद्देश्य के लिए एक समर्पित नीति होनी चाहिए।उदाहरण के लिए डिजिटल कामर्स ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) एक नीति है, जिसका एक मात्र उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं के लिए ई–कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है। ओएनडीसी के आने से पहले तमाम ई–कॉमर्स कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी और पैसे जलाने वाले बिजनेस मॉडल के अलावा खरीददारों और विक्रेताओं के शोषण के अनेक मामले प्रकाश में आए थे। ओएनडीसी के उद्देश्य में स्पष्टता थी, इसलिए उसके द्वारा ऐसी नीति तैयार की गई ताकि कंपनियों वकीलों या ग्राहकों या मीडिया द्वारा विरोधाभासी व्याख्या की कोई गुंजाइश ही ना हो। ओएनडीसी के माध्यम से आज एक कुशल व्यवहार व्यवसाय हो रहा है।

ऑनलाइन गेम्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का बहुराष्ट्रीय कंपनियां विरोध कर रही हैं। भारत में लगभग साढ़े तेरह हजार करोड़ का ऑनलाइन गेम का कारोबार है। इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को इसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद थी। जीएसटी दर बढ़ाई जाने के बाद यह कंपनियां देश में स्टार्टअप के बंद होने का रोना रो रही हैं।

स्वदेशी जागरण मंच का स्पष्ट मानना है भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराएं और सबसे बढ़कर भारतीय युवा शक्ति भारत की ताकत है। इनके लूट की खुली छूट नहीं दी जा सकती।

कई एक सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठनों द्वारा हेरफेर कर तैयार की गई सिफारिशों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी हितधारकों द्वारा वित्त पोषित संगठनों की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी शोध संस्थान की पहल की गयी है। उम्मीद की जानी चाहिए की स्वदेशी शोध संस्थान सार्वजनिक नीति अनुसंधान के मार्फत पनपने वाले पापाचार को दूर करने का सफल माध्यम बन कर उभरेगा तथा भारतीय मूल्यों परम्परा की रक्षा करते हुए भारतीय प्रज्ञा ज्ञान और मेधा को सबल प्रदान करेगा। ❑❑

अपना चावल बचाने की जरूरी पहल

वैश्विक रूप से दुनिया में चावल निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सा भारत का है, लेकिन जो हम निर्यात करते हैं, वह हमारी कुल पैदावार का 12 प्रतिशत है। भारत ने सावधानी बरतते हुए अभी गैर–बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, तो जाहिर है, दुनिया में अनाज की कीमतों पर असर पड़ेगा। अमेरिका में यह देखा जा रहा है कि चावल में 10 डॉलर का उछाल आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को यह क्यों करना पड़ा? यह इसलिए करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो भंडार है, उसमें आगे जाकर कमी आने की आशंका है। अभी जो खरीफ का समय चल रहा है, इसी सीजन में चावल की पैदावार होती है। फसल पर मौसम की मार पड़ी है। पहली बात तो यह है कि चावल के बड़े कटोरे पंजाब, हरियाणा में बाढ़ आई है। जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, उसके चलते माना जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों में धान फिर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जो रोपनी हो रही है, वह 15 अगस्त से पहले पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद देरी होगी, तो फसल और उत्पादन पर असर पड़ जाएगा।

मध्य प्रदेश के आगे दक्षिण भारत में तो 20 से 30 प्रतिशत बारिश कम हुई है, वहां भी उत्पादन कम होने की आशंका है। अभी अल नीनो की शुरुआत नहीं हुई है, अगर अल नीनो की मार पड़ती है, तो लगता है कि चावल की जो पैदावार होगी, वह चिंताजनक होगी। भंडार पर असर पड़ेगा, इसलिए भारत ने गैर–बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित किया है।

अभी हमारे पास एक जुलाई तक 7.1 करोड़ टन धान और गेहूं का भंडार है। अभी तो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है, लेकिन आने वाले दिनों में जो फसल की स्थिति है, उसे देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, बहुत अच्छा है। सही समय पर सही कदम है। पिछले साल देश ने देखा कि जब गेहूं की पैदावार में कमी हुई थी, तब भी बहुत अपेक्षा थी कि हम निर्यात करेंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह भी कहा गया था कि भारत दुनिया के लिए

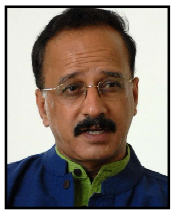

भारत ने इसे समय रहते समझ लिया है, अगर अनाज की समस्या को सुलझाना ही है, तो अमेरिका और यूरोप को आगे आना चाहिए। ध्यान रहे, मोटरकार ईंधन का इंतजार कर सकती है, लेकिन इंसान अनाज का इंतजार नहीं कर सकता। हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है।'

– देविंदर शर्मा

अन्नदाता होगा। यह भी कहा गया था, हम दुनिया की गेहूं की जरूरत को पूरा करेंगे, लेकिन यह गलत था। हमारे पास उतना भंडार नहीं है कि हम सारा कुछ निर्यात कर दें, अच्छा हुआ कि सरकार ने सुध ली और निर्यात रुका। अगर यह नहीं होता, तो दुनिया में हमें कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता।

कुछ ही दिन पहले एफसीआई ने कर्नाटक को चावल देने से मना किया, यह कहते हुए कि हमारे पास भंडार नहीं है, लेकिन जब निर्यात की बात आती है, तो हमारे यहां एक तबका है, जो खड़ा हो जाता है कि निर्यात अगर रुकेंगे, तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी।

मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ गरीबों को देने के लिए अनाज नहीं है और जब निर्यात की बारी आती है, तो हम कहते हैं निर्यात बढ़ना चाहिए। यह विरोधाभास है। आखिर हम किस लॉबी का बचाव करना चाहते हैं? जब हम पंजाब सूबे की बात करते हैं, तब कहा जाता है, पंजाब के किसानों ने पानी का निर्मम दोहन किया है। 138 ब्लॉक हैं, जिनमें से 109 ब्लॉक में पानी 'ब्लैक जोन' में पहुंच गया है। वहां सौ प्रतिशत से ज्यादा पानी खींचा जा रहा है। जब हम निर्यात करते हैं, तब हम कहते हैं, पंजाब खेती में विविधता लाए।

ज्यादा चावल उपजाने से पानी का नुकसान होता है। यह बहस हम सुनते आए हैं। पंजाब 99 प्रतिशत चावल बाजार को दे देता है। खुद एक प्रतिशत का ही उपभोग करता है। जब चावल की कमी होती है, तब पंजाब को कहा जाता है, सब भूल जाओ, हमें ज्यादा चावल चाहिए। एक तरफ, पानी की कमी का रोना और दूसरी तरफ, ज्यादा चावल की मांग। पंजाब में एक अर्थशास्त्री है एस एस जौहल, उन्होंने शोध करके बताया कि जब हम चावल

भारत ने इसे समय रहते समझ लिया है, अगर अनाज की समस्या को सुलझाना ही है, तो अमेरिका और यूरोप को आगे आना चाहिए। ध्यान रहे, मोटरकार ईंधन का इंतजार कर सकती है, लेकिन इंसान अनाज का इंतजार नहीं कर सकता।

का निर्यात करते हैं, तब हम अपने पानी का भी निर्यात करते हैं। प्रदेश में 12 से 1.3 करोड़ टन के बीच चावल की पैदावार होती है, जिसमें 48 से 52 अरब लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। पिछले साल हमने 2.2 करोड़ टन का निर्यात किया है। मतलब, 2.2 करोड़ टन चावल के साथ 88 अरब लीटर पानी का निर्यात किया है।

कहा जाता है, तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा और फिर भी हम पानी निर्यात करते हैं? चिंता सब जताते हैं, लेकिन बुनियादी रूप से कौन सोचता है? क्या चावल के साथ पानी निर्यात को रोकना नहीं चाहिए? आज ज्यादातर देश अपना पानी बचाने में लगे हैं। दुनिया के अनेक देश अपना लकड़ी भी निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि लकड़ी का आयात करते हैं, ताकि अपना नुकसान न हो। जब आप लकड़ी निर्यात करते हैं, तो आप अपने जंगल और जल को भी निर्यात करते हैं। ऐसे ही कोयला वाले देश भी करते हैं, भारत से कोयला मंगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जरूरी है, हम अपने पानी का बचाव करें। भारत में सावधानी बरतते हुए सिर्फ चावल का निर्यात ही नहीं रुका है। जो 1.5 मिलियन टन अनाज बायोफ्यूल के लिए दिया जाता है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आज जो वैश्विक स्थिति है, उसमें जब हमें जरूरत पड़ेगी, तब कोई भी देश हमारे पास नहीं आएगा।

चिंता मत कीजिए, दुनिया के पास बहुत अनाज है। अमेरिका के पास इतना ज्यादा अनाज है कि वह उसमें से नौ करोड़ टन अनाज बायोफ्यूल के लिए दे देता है। यूरोप में 1.2 करोड़ टन अनाज एथेनॉल उत्पादन के लिए दिया जाता है। ये देश अपने उपभोग में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन भारत को कहा जाता है कि आप दुनिया के अन्नदाता हो, तो आप अपने भंडार व अनाज हमारे लिए उपलब्ध कराओ।

भारत ने इसे समय रहते समझ लिया है, अगर अनाज की समस्या को सुलझाना ही है, तो अमेरिका और यूरोप को आगे आना चाहिए। ध्यान रहे, मोटरकार ईंधन का इंतजार कर सकती है, लेकिन इंसान अनाज का इंतजार नहीं कर सकता। हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है। जहां तक आम भारतीयों का सवाल है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास खूब भंडार हैं, 7.1 करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है, जो जरूरत से ज्यादा है, तो हमें कोई डर नहीं है और अभी तो नई पैदावार भी आनी है। ❑❑

https://www.livehindustan.com/blog/latest-blog/story-hindustan-opinion-column-26-july-2023-8487690.html

भारत का गौरव चंद्रयान–3
एक संक्षिप्त परिचय

भारत ने अन्तरिक्ष में एक और गौरवपूर्ण सफलता प्राप्त की, जब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान–3 का प्रक्षेपण किया गया। इस उपलब्धि के साथ भारत अमेरिका, अविभाजित रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा। इसके बाद लैंडर के 23–24 अगस्त के बीच चांद की सतह पर पहुंचने की आशा है। कुल 42 दिन में चंद्रयान–3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। लॉन्चिंग के बाद पहले चांद की कक्षा में पहुंचेगा फिर उसकी परिक्रमा करते हुए लैंड करेगा। इसने दूसरा ओरबिट रेंजिंग मेनूवर पूरा कर लिया है। इसकी लोकेशन 41,603 x 226 ओरबिट में है। चंद्रयान–3 करीब 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसको चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा जाएगा। क्योंकि चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल से अधिक बड़ा है। यहां जल उपलब्ध होने की संभावना है। यह खोज आंतरिक सौर मंडल की स्थितियों का एक अपरिवर्तित ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करेगी। इसके अलावा, इसके निकट के स्थान जो सदैव इसकी छाया में आच्छादित रहते हैं, उनमें जल की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। इसका रोवर इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह से जुड़ी जानकारियां भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा। इसके विषय में मूल भूत वैज्ञानिक जानकारी होना भी आवश्यक है जिससे इस उपलब्धि का वास्तविक अर्थों में उत्सव मनाया जा सके।

चंद्रयान–3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान–2 का अनुवर्ती मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था। पूर्व में विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की खोज की आवश्यकता अनुभव की गई जो वर्ष 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन से संभव है। कुल 43.5 मीटर लंबे चंद्रयान–3 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल है। चंद्रयान –3 इंटरप्लेनेटरी मिशन के प्रमुख तीन मॉड्यूल हैं– प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। यद्यपि इस ऑर्बिटर को चंद्रयान–2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाएगा। इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर व पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार करने तक सीमित रहेगा।

इसे जीएसएलवी एमके–3 द्वारा एसडीएससी, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किमी चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ (शेप) पेलोड का स्पेक्ट्रो–पोलारिमेट्री है। चंद्रयान –3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल (एलएम), प्रोपल्सन मॉड्यूल (पीएम), और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर नरम लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह का इन–सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर प्रयोगों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनद्वारा विकसित जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल–एमके 3 (जीएसएलवी–एमके 3) एक उच्च प्रणोदन क्षमता वाला यान है। यह एक

अपने देश के युवाओं को इस वैज्ञानिक उपलब्धि से प्रेरित करने के लिए विद्यालयों में विज्ञान के विशेष सत्र बुलाकर वाद–विवाद, चर्चा, विमर्श और प्रबोधन के आयोजन करने चाहिए जिससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़े और स्वयं तथा देश के विकास में उनकी सशक्त भागीदारी हो।

–विनोद जौहरी

तीन–चरणीय वाहन है, जिसे संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसका द्रव्यमान 640 टन है जो 8,000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) और 4000 किलोग्राम पेलोड को जीटीओ (जियो–सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट – जीटीओ) में स्थापित कर सकता है।

तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में 24 फरवरी को 25 सेकंड की नियोजित अवधि के लिए यह परीक्षण किया गया था।परीक्षण के दौरान सभी प्रणोदन पैरामीटर संतोषजनक पाए गए और भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाते दिखे।क्रायोजेनिक इंजन को पूरी तरह से एकीकृत उड़ान क्रायोजेनिक चरण का अनुभव करने के लिए प्रणोदक टैंकों, चरण संरचनाओं और संबंधित द्रव लाइनों के साथ और एकीकृ त किया जाएगा। चंद्रयान –3 में लॉन्चर संगतता, सभी आरएफ सिस्टम के एंटीना ध्रुवीकरण, कक्षीय और संचालित अवतरण मिशन चरणों के लिए स्टैंडअलोन ऑटो संगतता परीक्षण, और लैंडिंग मिशन चरण के लिए लैंडर और रोवर संगतता परीक्षण सुनिश्चित किए गए।

पूर्व में चंद्रयान–2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे। ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया था, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिये लैंडर और रोवर मॉड्यूल को अलग किया गया था। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था। इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी–एमके 3 द्वारा भेजा गया था।यद्यपि लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रैश–लैंडिंग की गई

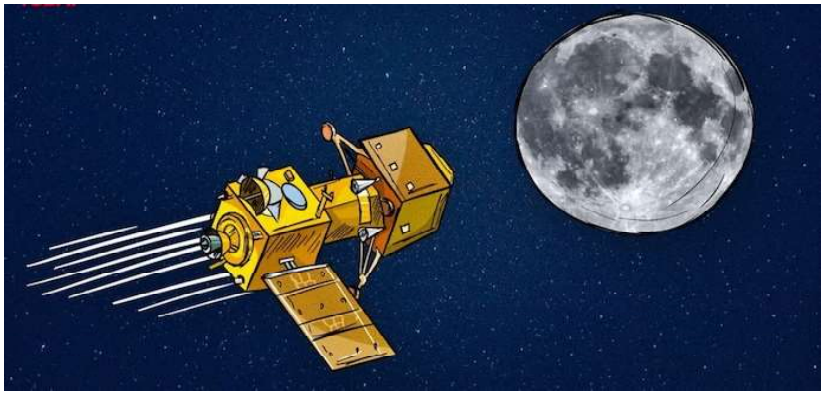

जिस कारण रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका था।

चंद्रयान–3 की कक्षाओं (ऑर्बिट) के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है।

1. ध्रुवीय कक्षा– एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर गुज़रता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है। इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब होता है। यहाँ से उपग्रह द्वारा पृथ्वी के लगभग हर हिस्से को देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है। इन उपग्रहों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे– फसलों की निगरानी, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओज़ोन सांद्रता को मापना या वातावरण में तापमान को मापना। ध्रुवीय कक्षा में स्थित लगभग सभी उपग्रहों की ऊँचाई कम होती है। एक कक्षा को सूर्य–तुल्यकालिक कहा जाता है क्योकि पृथ्वी के केंद्र और उपग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण संपूर्ण कक्षा में स्थिर रहता है।इन कक्षाओं को "लो अर्थ ऑर्बिट" के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑनबोर्ड कैमरा को प्रत्येक बार की जाने वाली यात्रा के दौरान समान सूर्य–रोशनी की स्थिति में पृथ्वी की छवियों को लेने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार यह उपग्रह को पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिये उपयोगी बनाता है। यह सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के ऊपर से गुज़रता है।

2. भू–तुल्यकालिक कक्षा– भू–तुल्यकालिक उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है। जब उपग्रह एक विशिष्ट ऊँचाई (पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी.) पर कक्षा में स्थित रहता है, तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है। जबकि भूस्थैतिक कक्षा भी भू–तुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण है। भूस्थिर उपग्रहों के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वृत्तीय गति हेतु आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिये पर्याप्त होता है। भू–तुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा को प्राप्त करने के लिये एक अंतरिक्षयान को पहले भू–तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में लॉन्च किया जाता है। जियो–सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से अंतरिक्षयान अपने इंजन का उपयोग भूस्थैतिक और भू–तुल्यकालिक कक्षा में स्थानांतरित होने के लिये करता है।

अपने देश के युवाओं को इस वैज्ञानिक उपलब्धि से प्रेरित करने के लिए विद्यालयों में विज्ञान के विशेष सत्र बुलाकर वाद–विवाद, चर्चा, विमर्श और प्रबोधन के आयोजन करने चाहिए जिससे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़े और स्वयं तथा देश के विकास में उनकी सशक्त भागीदारी हो। ❑❑

ऑनलाईन खेलों पर जीएसटी है सही कदम

हाल ही में भारत की जीएसटी काऊंसिल ने ऑनलाईन गेम्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। उसके बाद जीएसटी काऊंसिल के उस निर्णय पर घमासान जारी है। हालांकि ऑनलाईन गेम खेलने वालों की ओर से तो कोई आपत्ति तो ध्यान में नहीं आई है, लेकिन इस गेम को खिलाने वालों (एप कंपनियों) की ओर से आपत्ति जरूर आई है। इन ऐप कंपनियों का कहना है कि ऑनलाईन गेमों पर जीएसटी लगने से उन्हें नुकसान होगा। कुछ दिन पहले 180 गेम कंपनियों की ओर से जीएसटी कांऊसिल को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है।

क्या हैं गेमिंग कंपनियों के तर्क?

गेमिंग कंपनियों का पहला तर्क यह है कि पूर्ण जमा राशि पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव इस 'उद्योग' के विकास पथ को उलट देगा। वर्तमान कंपनियों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही छोटी कंपनियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जायेगा। इन कंपनियों का दूसरा तर्क यह है कि इस क्षेत्र में नए घरेलू और विदेशी निवेशकों का निवेश हतोत्साहित होगा। उनका यह भी कहना है कि यही नहीं कि गेमिंग उद्योग इस निर्णय से प्रभावित होगा, पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम ही इससे प्रभावित होगा।

हालांकि सरकार की ओर से जीएसटी लगाने के निर्णय के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है, लेकिन यह सच है कि देश के विभिन्न हलकों में इन ऑनलाईन गेमों में युवकों की बढ़ती लत और उसके कारण आ रही विसंगतियों और संकटों के कारण, भारी चिंता जरूर व्याप्त थी, जिसके बारे में सरकार भी अनभिज्ञ नहीं थी। ग़ौरतलब है कि इन ऑनलाईन गेमों को कुल 4 करोड़ लोग और नियमित रूप से 1 करोड़ लोग खेलते हैं। सरकार का कहना है कि अभी तक इन खेलों पर मात्र 2 से 3 प्रतिशत का ही जीएसटी लगता है जो आम आदमी द्वारा खाने पीने की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी से भी कम है। 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने से सरकार को 20000 हज़ार करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है।

सरकार द्वारा ऑनलाईन खेलों पर उच्चतम दर से जीएसटी लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार एप्स के जरिए चलने वाले जुए अथवा तथाकथित कौशल आधारित खेलों में पैसा डुबोते नासमझ अथवा जानकारी के अभाव से ग्रस्त युवाओं की बदहाली के प्रति जागरूक है, और वो इसे रोकना चाहती है।
–स्वदेशी संवाद

समाज और सरकार की क्या है चिंता?

पिछले कुछ सालों में कई प्रकार की ऑनलाईन गेम्स का भी प्रादुर्भाव हुआ है। कई बड़ी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही एप्स का विज्ञापन तो खेल और मनोरंजन क्षेत्र की बड़ी हस्तियां तक कर रहीं हैं। हालांकि इन्हीं विज्ञापनों में एक त्वरित चेतावनी भी होती है, 'इन गेम्स को सावधानी से खेलें, इनकी लत लग सकती है'। दरअसल आज हमारे युवा इन मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थित ऐप्स और गेम्स के चुंगुल में फंसते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से देश में इंटरनेट और मोबाईल के विस्तार के कारण इस रियल मनी गेमिंग 'उद्योग' का काफी विस्तार हुआ है और इनका व्याप बढ़ता ही जा रहा है।

शेयर ट्रेडिंग संबंधित खेल, क्रिप्टो आधारित गेम्स, रम्मी, लुडो, आभासी खेलों (फेंटेसी स्पोर्ट) समेत कई ऑनलाईन और एप आधारित खेलों को 'रियल मनी गेम्स' कहा जाता है, क्योंकि ये गेम पैसे या ईनाम के लिए खेले जाते हैं। कहा जाता है कि इन खेलों में से कुछ कौशल आधारित हैं और कुछ संयोग आधारित (यानि जुआ) हैं। चाहे संयोग आधारित यानि जुए के खेल हों या कौशल आधारित, सभी ऑनलाईन खेलों का तेजी से विस्तार हुआ है

और इन एप्स और वेबसाईटों को बढ़ावा देने वाली कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इन खेलों के कारण हमारे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

युवाओं का भविष्य बिगाड़ते ये खेल

जब से इन खेलों का प्रादुर्भाव हुआ है, कई युवाओं ने कर्ज में फंसकर अपनी जान गँवा दी है। समझना होगा कि इन खेलों में जीतने की संभावना बहुत कम होती है, तो भी इन एप्स के कारण जुएं की लत के चलते युवा भारी कर्ज उठाने लगते हैं और उन्हें न चुका पाने के कारण उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आज बड़ी–बड़ी क्रिकेट हस्तियों द्वारा विज्ञापनों के कारण ड्रीम 11 सरीखे एप्स पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए हैं। लुडो जैसे एप मनोरंजन क्षेत्र की एक बड़ी हस्ती कपिल शर्मा और कई अन्य सेलिब्रिटीज़ द्वारा अनुमोदित की जा रही है। इन एप्स में फंसकर आत्महत्या करने वाले अधिकांश 18 से 25 वर्ष के युवा हैं, जिनमें विद्यार्थी, प्रवासी मजदूर और व्यापारी शामिल हैं।

कौशल या संयोग

ड्रीम–11 के संदर्भ में अधिकांशतः न्यायालयों ने उसे यह कहकर उचित ठहराया है कि ये जुआ नहीं बल्कि कौशल का खेल है। उसके बावजूद 6 राज्य सरकारों ने ऐसे आभासी क्रिकेट प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित किया है अथवा अनुमति नहीं दी है। इसी प्रकार आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 132 एप्स को प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है।

चाहे यह मान भी लिया जाए कि आभासी क्रिकेट खेल में जीतने के लिए कुछ भी संयोग नहीं है, इसलिए यह जुआ नहीं, लेकिन कुछ खेल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आभासी क्रिकेट जुआ ही है और इसके कारण जुए के व्यवहार का रोग लग सकता है। इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां यह मानने के लिए तैयार नहीं कि इससे लत पड़ सकती है क्योंकि दांव की राशि बहुत कम है। लेकिन वास्तविकता इससे हटकर है। इन खेलों में हार कर लाखों रूपए के कर्जे के कारण आत्महत्या करने वालों के बारे में जानकारी से यह बात गलत सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस विषय में इन अभासी खेल एप्स कंपनियों के दावों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन खेलों के संबंध में कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है और यह व्यवसाय स्वनियामक यानि सेल्फ रेगुलेटिड ही है। इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के दावों और वास्तविकता में बहुत अंतर है।

अभी न्यायालयों को यह तय करना बाकी है कि क्या पैसों का दांव लगाने वाली तथाकथित कौशल आधारित गेम जुआ हैं, लेकिन यदि किसी भी खेल में संयोग का अंश रहता है तो वह जुआ ही होता है और देश के कानून के अनुसार यह वैधानिक नहीं हो सकता। यह भी देखने में आ रहा है कि कई एप्स कौशल आधारित खेलों की आड़ में विशुद्ध जुए के प्लेटफॉर्म चला रही हैं। महत्वपूर्ण है कि इन एप्स में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेशकों खासतौर पर चीनी निवेशकों ने पैसा लगाया हुआ है, और उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को जुए की लत लगाना है। इन एप्स का डिजाईन ही लत लगाने वाला है। यही नहीं कई तथाकथित कौशल आधारित गेम्स के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटा भी जा रहा है। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक ने यह टिप्पणी दी है कि इन कौशल आधारित गेम्स के नतीजों को मशीनी छेड़छाड़ से प्रभावित किया जा सकता है।

जीएसटी का क्या होगा प्रभाव?

हालांकि सरकार कृषि जिन्सों को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाती ही है। देश में कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, जिन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारे देश में जुआ, वैश्यावृति, चोरी–डकैती जैसे कार्यकलाप वैधानिक रूप से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके उत्पादन और उपभोग को हतोत्साहित कर उन्हें न्यूनतम करना सरकार का सामाजिक दायित्व होता है। उदाहरण के लिए देश में तम्बाकू उत्पादों, शराब इत्यादि पर अधिकतम टैक्स लगता रहा है। वर्ष 2023–24 के बजट में वित्तमंत्री ने ऊंचे जीएसटी के अलावा सिगरेट पर अतिरिक्त कर भी लगाया है। ऑनलाईन रियल मनी आभासी खेल चूंकि अभी तक ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं हो पाएं हैं कि ये जुआ हैं अथवा कौशल के खेल, लेकिन चूंकि इन खेलों में रूपया गंवाने की बड़ी संभावना है, इसलिए ऐसे खेलों को कम टैक्स लगा, प्रोत्साहित किया जाना सामाजिक हित के खिलाफ है।

जीएसटी कांऊसिल द्वारा इन आभासी खेलों पर अधिकतम दर से जीएसटी लगाना बिल्कुल उपयुक्त कदम है, क्योंकि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। युवाओं के बीच इन खेलों के प्रति बढ़ती लत और उसके कारण उनको होने वाले भारी वित्तीय नुकसान के कारण उन पर बढ़ते कर्ज और आत्महत्या जैसी परिस्थिति को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर सरकार द्वारा इन खेलों पर उच्चतम दर से जीएसटी लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार एप्स के जरिए चलने वाले जुए अथवा तथाकथित कौशल आधारित खेलों में पैसा डुबोते नासमझ अथवा जानकारी के अभाव से ग्रस्त युवाओं की बदहाली के प्रति जागरूक है, और वो इसे रोकना चाहती है। ❑❑

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भारत के आर्थिक विकास पर भरोसा

हाल ही में कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने भारत के भविष्य में होने वाले आर्थिक विकास को लेकर प्रतिवेदन जारी किए हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच इन प्रतिवेदनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए भविष्य का एक चमकता सितारा बताया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज संस्था मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत निश्चित ही विकास की एक लम्बी लहर के शुरुआती दौर में पहुंच गया है, और विकास की यह लहर लम्बे समय तक चलने वाली है। उक्त संस्था का मानना है कि भारत के मैक्रो संकेतक लचीले बने हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 6.2 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। संस्था ने भारत का स्टेट्स 'अंडरवेट' रेटिंग के बाद 'बराबर' रेटिंग से भी आगे बढ़ाते हुए 'ओवरवेट' रेटिंग में कर दिया है। क्योंकि, संस्था को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी। संस्था की प्रक्रिया में भारत पूरे विश्व में अपने 6ठवें स्थान से पहिले स्थान पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रतिवेदन जारी किया है। जिसमें, बताया गया है कि वित्त वर्ष 2030–31 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 6.7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से लेकर वित्तीय वर्ष 2030–31 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ेगी। इस विकास दर के चलते भारतीय नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान के स्तर 2,500 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2031–32 तक 4,500 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो जाएगी। हालांकि इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था में मातृशक्ति की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत के कुल वर्कफोर्स में मातृशक्ति की भागीदारी केवल 24 प्रतिशत थी। प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि भारत के लिए सेवा क्षेत्र से निर्यात आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा इंजिन साबित होने जा रहा है।

अभी हाल ही में देखा गया है कि न केवल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों बल्कि विदेशी निवेशकों एवं विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है।

– प्रहलाद सबनानी

एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, वर्ष 2030 तक स्टार्टअप के क्षेत्र में वेंचर कैपिटल फंडिंग वर्तमान की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलोजी, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, ड्रोंस रोबोटिक्स और क्लीन टेक्नोलाजी जैसे नए क्षेत्रों में भारत को सबसे अच्छा लाभ मिलने वाला है। इन क्षेत्रों में होने वाला पूंजी निवेश वर्तमान में चालू दशक के अंत तक भारत की औसतन 6.7 प्रतिशत की विकास दर में 53 प्रतिशत की हिस्सेदारी करने वाला है। साथ ही, भारत के उपभोक्ता बाजार का आकार भी वर्ष 2022 के 2.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2031 बढ़कर 5.2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, अर्थात वर्तमान की तुलना में दुगने से भी अधिक आकार का।

वैश्विक सलाहकार संस्था अर्नस्ट एंड यंग (ई वाय) ने "इंडिया एट 100: रीयलाईजिंग द पोटेंशियल आफ 26 ट्रिलियन डॉलर इकानोमी" नाम से जारी एक विशेष प्रतिवेदन के माध्यम से बताया है कि कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध एवं वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी, भारत के अमृत काल के दौरान, वर्ष 2047 तक भारतीय

अर्थव्यवस्था का आकार 26 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। शीघ्र ही, वर्ष 2028 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2036 में 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 में प्रत्येक भारतीय की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 15,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी, ये आज के स्तर से 7 गुना से भी अधिक है। वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। दरअसल भारत में भारी क्षमताएं मौजूद हैं और आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति पूरे वैश्विक आर्थिक मंच को प्रभावित करने जा रही है।

फायनांशियल टाइम्स के मुख्य अर्थशास्त्री श्री मार्टिन वुल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि अब यह लगभग निश्चित आभास होने लगा है कि आगे आने वाले लम्बे समय (10 से 20 वर्षों के दौरान) तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कोरोना महामारी के बाद की विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सम्हाला है बल्कि अन्य देशों की मदद के लिए भी इस दौरान अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इन्हीं कारणों के चलते वैश्विक स्तर पर कई अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं।

एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन एवं वित्तीय सेवा कम्पनी मोर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने भी एक प्रतिवेदन जारी कर कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की दृष्टि से अगला दशक भारत का होने जा रहा है। इस सम्बंध में उक्त प्रतिवेदन में कई

वैश्विक स्तर पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में इस समय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है।

कारण गिनाए गए हैं, जिनके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान स्तर 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसी प्रकार, भारत का पूंजी बाजार भी अपने वर्तमान स्तर 3.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर पर 11 प्रतिशत की, चक्रवृद्धि की दर से, वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए अगले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। भारत में घरेलू मांग के लगातार मजबूत होने से एवं भारत में डिजिटल क्रांति के कारण भारतीय नागरिकों की आय में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का पांचवा हिस्सा भारत से निकलेगा, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के उक्त विचार सत्य होते भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सेवा क्षेत्र से जुड़ी सर्विस पीएमआई के माह जुलाई 2023 के आंकड़े बता रहे हैं कि, एसएंडपी ग्लोबल का इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई का स्तर जुलाई 2023 में 62.3 पर रहा है जो कि पिछले 13 वर्षों का उच्च स्तर है और इसके जरिए भारत के सेवा क्षेत्र में हो रहे शानदार विकास का पता चलता है। सेवा क्षेत्र से निर्यात भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद (एसईपीसी) ने यह उम्मीद जताई है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत से सेवाओं का निर्यात 400 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत से सेवा क्षेत्र में निर्यात वित्तीय वर्ष 2021–22 के 254 अरब डॉलर से 42 प्रतिशत अधिक अर्थात 323 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। परिषद के चेयरमैन ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सेवा क्षेत्र से 300 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तव में यह 323 अरब डॉलर का रहा है। भारत के विकास में सेवा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र का ही रहता है एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में भी सेवा क्षेत्र का अहम स्थान है।

अब वैश्विक स्तर पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों – विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीयन यूनियन, एशियाई विकास बैंक, आदि द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में इस समय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहां प्रशन्न उठता है कि क्या वर्ष 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत सहारा दे सकता है। इसका उत्तर सकारात्मक रूप में ही मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि न केवल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों बल्कि विदेशी निवेशकों एवं विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। ❑❑

लेखक– सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.

केंद्र सरकार के प्रयास से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार

एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जीवन रेखा बढ़ी है, तो तस्वीर का धुंधला पहलू यह भी सामने आना लगा है कि जो चीजें हमें प्रकृति से आसानी से मिल जाती हैं, जिन तक सहज पहुंच है, उन्हीं का अब आम आदमी को ज्यादा अभाव होने लगा है। ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित हवा, पानी, धूप मिल जा रही है, लेकिन नगरों और महानगरों में प्रकृति से मिलने वाली इन अनमोल चीजों का भी संकट बदलते समय के साथ बढ़ता जा रहा है।

यदि कोरोना प्रकोप के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में मचे हाहाकार की घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो अब इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के देशों में जीवन रेखा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के समग्र प्रयासों का परिणाम है कि अपने समय की जानलेवा बीमारियां टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, पीलिया, डायरिया आदि पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। दुनिया के देशों में बाल मृत्यु दर लगभग आधी रह गई है तो प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर भी करीब एक तिहाई रह गई है। संस्थागत प्रसव ने हालातों में तेजी से सुधार किया है। दुनिया के अधिकांश देशों में संक्रामक रोगों का असर भी कम हुआ है, तो डेंगू, स्वाईन फ्लू व इसी तरह की कुछ जानलेवा बीमारियां सामने आने लगी हैं।

पिछले कुछ दशकों से हमारे देश ही नहीं दुनिया के लगभग अधिकांश देशों में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके लिए वैक्सिनेशन अभियान और सरकारों द्वारा अनवरत रूप से चलाए जाने वाले अवेयरनेस और नियंत्रण अभियानों से हालातों में तेजी से सुधार हुआ है। लोगों की जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के अपवाद को अलग कर दिया जाए तो जहां 2000 में औसत आयु 67 साल होती थी वह 2022 तक बढ़कर 73 साल हो गई है। यानी कि 25 सालों में छह साल अधिक जीने लगे हैं आम नागरिक। यह अपने आपमें बड़ी उपलब्धि है, सरकारों और स्वास्थ्य सेवाओं की।

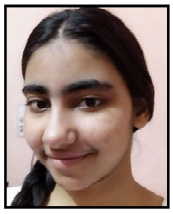

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय पहल की है। आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार हर भारतीय को रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कर रही है। सरकार के इन प्रयासों का असर अब जनजीवन में दिखने लगा है।

–वैदेही

यदि हमारे देश की ही बात करें तो जच्चा–बच्चा सुरक्षा अभियान के तहत महिला के प्रेगनेंट होने के साथ से ही नियमित जांच, दवा और टीकों का अभियान चलने के साथ ही प्रसव के बाद बच्चों की सुरक्षा और भविष्य में बीमारी न हो, इसके लिए नवजात बच्चों को मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक के साथ ही 5–7 साल की उम्र होने तक जिस तरह से अलग–अलग बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके लगाये जा रहे हैं और सरकारी डिस्पेंसरियों में वार विशेष को टीका लगाने की व्यवस्था होने से लोगों में जागरूकता आई है और इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगा है। टीकाकरण और समय समय पर एनिमिया, दस्त निरोधक, कृमि नाशक दवाएं अभियान चलाकर उपलब्ध कराने से सेहत के क्षेत्र में लगातार सुधार आया है। यह वास्तव में चिकित्सा जगत की बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए और इसके लिए सरकारों व स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो पाया है।

एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जीवन रेखा बढ़ी है तो तस्वीर का धुंधला पहलू यह भी सामने आना लगा है कि जो चीजें हमें प्रकृति से आसानी से मिल जाती हैं, जिन तक सहज पहुंच है उन्हीं की डेफिसिएंसी ज्यादा होने लगी है। यह सब हमारे रहन–सहन, खान–पान और दौड़ती भागती जिंदगी का परिणाम है। आज लोगों में विटामिन डी या सी की कमी आम होती जा रही है। जबकि हम जानते हैं कि चंद मिनटों यानी कि 5–7 मिनट प्रतिदिन धूप सेवन से विटामिन डी की डेफिसिएंसी को दूर किया जा सकता है, पर हालात यह हो गए हैं कि हम केमिकल से तैयार दवा लेने को तैयार हैं, परंतु पांच मिनट धूप सेवन के लिए हमारे पास समय की कमी है। हालांकि मेट्रोसिटीज में

केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय वांग्मय में मनुष्य के सौ वर्ष जीने की परिकल्पना में वर्णित आयुर्वेद के विस्तृत प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए आयुष विभाग के जरिए गतिविधियां तेज कर दी हैं। वैकल्पिक स्वास्थ्य सुविधा के रूप में सरकार चरणबद्ध तरीके से आयुर्वेद के विकास में अपेक्षित योगदान कर रही है।

गगनचुंबी अट्टालिकाओं के कारण सूर्य भगवान से साक्षात्कार करना लगभग मुश्किल भरा हो जाता है। इसी तरह से काम धंधे की भागदौड़ में धूप सेवन जैसी प्रकृति से सीधे साक्षात्कार का अवसर लाभ नहीं ले पाते हैं। और तो और रंग काला हो जाएगा इसी के चलते धूप से परहेज किया जाने लगा है। इसी तरह से बच्चों का मिट्टी में खेलना तो अब सपना रह गया है। परंपरागत खेल जो शारीरिक व मानसिक व्याधियों से बचाने में सहायक होते थे, वह आज कहीं नैपथ्य में चले गए हैं। आज पैसा खर्च कर जिम में जाकर पसीना बहाने को तैयार हैं, पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले उपहार धूप, हवा पानी से दूर होते जा रहे हैं। एक कारण बढ़ता प्रदूषण भी है। इस सबसे अधिक चिंतनीय यह होता जा रहा है कि आज की पीढ़ी तेजी से डिप्रेशन की शिकार होती जा रही है। प्रतिस्पर्धा का यह दौर डिप्रेशन के रूप में सामने आ रहा है और सेहत के मोर्चे पर इसके दुष्परिणाम तेजी से सामने आने लगे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय वांग्मय में मनुष्य के 100 वर्ष जीने की परिकल्पना में वर्णित आयुर्वेद के विस्तृत प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए आयुष विभाग के जरिए गतिविधियां तेज कर दी हैं। वैकल्पिक स्वास्थ्य सुविधा के रूप में सरकार चरणबद्ध तरीके से आयुर्वेद के विकास में अपेक्षित योगदान कर रही है। करोना महामारी के दौरान जिन लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा उनमें इसके प्रति भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है वही जड़ी बूटियां के सहारे अपने आप को ठीक रखने वाले अधिकांश लोग आयुष उत्पादों के सच्चे एंबेसडर भी बने हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय पहल की है। आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार हर भारतीय को रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कर रही है। सरकार के इन प्रयासों का असर अब जनजीवन में दिखने लगा है। ❑❑

बाढ़ का एक प्रमुख कारण बढ़ता तापमान भी

प्रकृति अपने मूल में जीवन है। लेकिन उससे छेड़छाड़ का रास्ता अपनाकर मानव ने अपने लिए विपरीत परिस्थितियां ही पैदा की है। यह तब भी हो रहा था जब मानव विकास की प्रक्रिया में था और आज भी हो रहा है जब दुनिया भर में विकास अपने चरम पर है। प्रारंभ का मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेता था जितने कि उसे सख्त जरूरत थी लेकिन आज के दौर में मनुष्य इतना स्वार्थी और लालची हो गए हैं कि अपनी बढ़ती आवश्यकताओं पर रोक लगाना, उनके बस की बात नहीं है। अपनी जरूरत के लिए हम प्रकृति से लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसी लापरवाही का नतीजा है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बरसा आदि का चक्र भी गड़बड़ होता जा रहा है। भारत के ही भूगोल में देखें तो एक ही समय पर कुछ हिस्सों में भयावह बाढ़ है तो कुछ हिस्सों में भयंकर सूखा।

इस साल जुलाई में जब भारत में बारिश में कई बड़े शहरों में बाढ़ के हालात पैदा किया ठीक उसी समय यूरोप के लोग भीषण गर्मी से परेशान दिखे।वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि अधिकांश यूरोपीय देशों में इस साल जुलाई के दिनों में तापमान अन्य वर्षो की तुलना में अधिक था। पिछले साल भी वहां बढ़ते हुए तापमान की हालत ऐसी ही थी। राहगीरों को गर्मी से बचने के लिए विशेष उपाय करने पड़े थे। गर्मी से निजात पाने के लिए यूरोपीय और अमेरिकी देशों में जहां एयर कंडीशनर की की खरीद के लिए दुकानों पर भीड़ लगी थी। ठीक उसी समय देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ से दो–चार हो रही थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके भी जलमग्न थे।

दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण पर हो रहा है बल्कि इसका वास्तविक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। यूरोपीय का आदमियों की विज्ञान सलाहकार परिषद की मानें तो 1980 के बाद दुनिया भर में बाढ़ की घटनाएं लगभग दोगुने से अधिक बढ़ गई है। इसलिए जरूरी है कि राहत और बचाव के इंतजामों के साथ–साथ बदलते मौसम पर भी शोध होना चाहिए। तापमान बढ़ने से पर्वतों की बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। चक्रवात और तूफान जैसी मौसमी घटनाओं के चलते भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश

सरकार के साथ–साथ देश के आम लोगों को भी पर्यावरण के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए सामूहिक भागीदारी के भाव के साथ आगे आना होगा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए कार्यक्रम बनाकर रणनीतिक तैयारी करनी होगी। अगर यह नहीं हुआ तो हमारे शहर और गांव आगे भी डूबते रहेंगे।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

के हालात बने रहते हैं जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा हमेशा होता है। बाढ़ का एक कारण नदी का अतिप्रवाह है। दरअसल भारी वर्षा होने पर, बर्फ या ग्लेशियर पिघलने पर, चक्रवात या तूफान आने पर, बांध या बैराज से अधिक जल छोड़े जाने या नदियों में अत्यधिक गाद जमा हो जाने के कारण नदियों में अति प्रवाह जैसा उत्पन्न हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली की बाढ़ है। जब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ गया तब दिल्ली स्थित यमुना बेराज यमुना नदी के इस प्रवाह को नियंत्रित करने में असमर्थ साबित हुआ। नदियों नालों के बहाव क्षेत्र के आसपास भारी संख्या में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण बहाव क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसलिए अधिक बारिश होने पर पानी का दबाव बढ़ जाता है, आसपास के क्षेत्र में जल प्रवाहित होने लगता है, जिससे वहां जल भराव की स्थिति बन जाती है। कई बार तो बांध और बैराज को बिना सूचना दिए ही अचानक पानी छोड़ दिए जाने के कारण नदियों के तट पर बसे शहरों में बाढ़ की नौबत आ जाती है। पहले की तुलना में अब आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है लेकिन हम आज भी बाढ़ नियंत्रण के पुराने इंतजामों पर ही निर्भर हैं। शहरों में बाढ़ का प्रमुख कारण अनियोजित शहरीकरण है। हर साल आने वाली बाढ़ से देश में सैकड़ों लोगों की जाने चली जाती हैं हजारों हजार लोगों को आर्थिक नुकसान होता है, वही भारी मात्रा में पशुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। बाढ़ के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, वही बाढ़ के निकलते ही कई तरह की भयानक संक्रामक बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में बाढ़ को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उन्हें फिर से जीवन में लौटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। भारत में आने वाली बाढ़ से हर साल लगभग 75 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित होती है और करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान होता है।आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में बाढ़ की वजह से लगभग 54 लाख लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा था।

अत्यधिक बारिश होने के कारण शहरों में पानी भरने लगता है। जल निकास प्रणालियों के ठीक ना होने के कारण जल इधर–उधर फैल जाता है। घरों और उद्योग धंधों का कचरा सीवेज प्रणाली से बह कर निकलता है, जबकि वर्षा जल प्रणाली से बारिश का पानी निकलता है। शहरों में आबादी बढ़ने के कारण सिवेज प्रणाली की क्षमता कम हो जाती है और नालों से पानी उफनने लगता है।

पूरे देश में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 1952 से लेकर 2018 के 66 सालों में देश में बाढ़ से एक लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं। अब तो राजस्थान में भी बढ़ आने लगी है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं।देश के कई एक रिवर बेसिन तबाही के इलाके साबित हुए हैं हर साल सूखे दिनों में लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बरसात में बाढ़ सब कुछ बाहर ले जाती है। अनियमित मानसूनी पैटर्न और कुछ इलाकों में कम और कुछ इलाकों में अधिक बरसात इस तबाही को कुछ इलाकों में और ज्यादा बढ़ा देती है।

ऐसे में सरकार के साथ–साथ देश के आम लोगों को भी पर्यावरण के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए सामूहिक भागीदारी के भाव के साथ आगे आना होगा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए कार्यक्रम बनाकर रणनीतिक तैयारी करनी होगी। अगर यह नहीं हुआ तो हमारे शहर और गांव आगे भी डूबते रहेंगे। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

सरकारें पशुओं की भी सुधि ले

हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ और भयंकर बारिश की शुरुआत असम से हुई और फिर कई प्रांतों में बाढ़ की विनाश लीला दिखने लगी। देश की राजधानी दिल्ली में तो 1978 के बाद यानी 48 सालों के बाद भयावह बाढ़ आई जिसने पूरे देश को वैसे ही अचंभित किया जैसे मुंबई, चेन्नई, केरल या फिर श्रीनगर की बाढ़ ने पूर्व में किया था।देखते ही देखते 11 राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। प्रशासन भी जरूरी काम समझ कर राहत और बचाव काम में जुट गया।

शहरों में तो सरकार के साथ–साथ कई प्रकार के स्वयंसेवी संगठन भी बचाव और राहत के लिए आगे आ जाते हैं लेकिन ग्रामीण भारत को आज भी कमोबेश उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है।ग्रामीण भारत में बाढ़ से हर साल बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है, फसली क्षेत्र की बहुत हानि होती है। गरीबों के घर उजड़ जाते हैं पशुओं के बाड़े नष्ट हो जाते हैं। गांव में मानव के साथ–साथ पशुओं की भी भारी हानि होती है। वर्ष 2022–23 की बाढ़ का आकलन देखें तो देश मैं बाढ़ से 18.54 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित रहा। इस दौरान 1997 लोगों की मौत हुई जबकि 30615 पशु मृत पाए गए। बाढ़ में जिनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दुख की बात है कि देश में आपदाओं के वक्त पशुओं को बचाने के लिए बुनियादी तंत्र तक नहीं है।जब कभी सूखा पड़ता है तो कई राज्यों में पशुओं के लिए कुछ इंतजाम होते हैं पर बाढ़ में तो सारी मशीनरी मनुष्य को बचाने में लग जाती है और बेजुबान पशु ईश्वर के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं।पशुओं को बचाने के लिए ना तो किसी राज्य में कोई प्रशिक्षित टीम है ना उनके लिए अलग कैंप की तैयारी की जाती है और ना ही उनके लिए पहले से चारा पानी का कोई इंतजाम होता है। बाढ़ की आपदा के समय पशुओं के लिए आवश्यक दवाइयों का अभाव तो होता ही है पशु चिकित्सक भी खोजे नहीं मिलते।

मनुष्य का जीवन सर्वोपरि है उसे उच्च प्राथमिकता के साथ डील किया जाना चाहिए लेकिन आपदाओं के वक्त पशुओं को बचाने के लिए भी किसी ठोस तंत्र की बात अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक पशु प्रधान देश भी है।

–शिवनंदन लाल

पशु संपदा के मामले में भारत दुनिया में सबसे धनी देश है। दुनिया का सबसे अधिक पशुधन भारत के पास है। दुनिया की भैंसों का 57 प्रतिशत और कुल मवेशियों का करीब 15 प्रतिशत भारत में है। बड़ी संख्या में लोग पशुपालन में लगे हैं जिनमें छोटे किसान सबसे अधिक 87 प्रतिशत तक है। दूध उत्पादक किसानों में 70 प्रतिशत के पास एक से तीन पशु हैं। अनेक भूमिहीनों तथा वंचित वर्ग के लोगों की आजीविका पशुपालन से ही चलती है। एक हेक्टेयर से कम रकबा वाले किसानों के पास 37 प्रतिशत पशुधन है। इन सब के बूते ही भारत दूध उत्पादन में दुनिया में शीर्ष पर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल

औसतन बाढ़ से 75 हजार से एक लाख पशु मर जाते हैं। इनमें काफी संख्या में दुधारू पशु भी होते हैं। वर्ष 2000 से 2014 के बीच देश में लगभग 12 लाख जानवरों की मौत आपदाओं से हुई। हाल के सालों का आंकड़ा देखें तो 2015 में 50000 पशु मरे, वही 2016 में 22367 पशु मर गए। वर्ष 2017 में 26673, वर्ष 2018 में 60279 पशु मर गए थे। वर्ष 2019 में 25852 पशु तथा 2020 में 45463 पशुओं की मौत हो गई थी। आपदाओं में बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुल 334 टीमें देश के विभिन्न भागों में तैनात हुई थी। बचाव टीम ने इस दौरान लगभग 98962 लोगों को बचाया लेकिन मात्र 617 पशुओं को बचाने में ही कामयाब हुए।

जब भी कोई बाढ़ या अन्य आपदा आती है तो सबसे पहले मानव जाति के बारे में सोचा जाता है। हम पशु को धन मानते हैं लेकिन आपदाओं में उनको कैसे बचाया जाए इस बारे में कुछ नहीं सोचते। पशुओं को लेकर लोगों में जागरूकता का भी अभाव है।आपदा के समय बड़े–बड़े नेता हेलीकॉप्टरों पर बैठकर हवाई सर्वेक्षण करने लगते हैं लेकिन पशुओं को आपदा प्रबंधन का हिस्सा बनाने की बात नहीं होती। तमाम पशु खूटे से बधे बधे ही डूब कर मर जाते हैं। दुधारू पशुओं के मर जाने से गरीब किसान की रीढ़ टूट जाती है। लेकिन विडंबना पूर्ण है कि सरकार के पास पशुओं के मरने से होने वाली आर्थिक क्षति का न तो कोई आंकड़ा है और ना ही इस नुकसान की भरपाई का कोई तंत्र।

पशु ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है और करोड़ों परिवार का पेट पशुओं से पलता है। देश में पशु चिकित्सकों का ढांचा बहुत कमजोर है। लगभग 15000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक है जबकि कायदे से 5000 पशुओं पर एक चिकित्सक होना चाहिए। आपदा प्रबंधन का काम पहले कृषि मंत्रालय के तहत था अब गृह मंत्रालय के पास है। आपदा में पशुओं के मरने संबंधी सवालों को संसद यह कहकर टाल देती है कि यह राज्यों का विषय है। कुछ राज्यों में दुधारू पशु जैसे भैंस, गाय, ऊंट के मामले में 30000 रूपये तक और भेड़ बकरी सूअर के मामले में 3000 रूपये तक की मदद का प्रावधान है। इसी तरह कुछ राज्यों में बछड़ा, गधा, खच्चर के मामले में 16000 रूपये तक के मुआवजे की बात है, लेकिन लाल फीताशाही की जकड़न के कारण यह मदद शायद ही किसी पीड़ित तक पहुंच पाती है। ठीक है कि मनुष्य का जीवन सर्वोपरि है उसे उच्च प्राथमिकता के साथ डील किया जाना चाहिए लेकिन आपदाओं के वक्त पशुओं को बचाने के लिए भी किसी ठोस तंत्र की बात अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक पशु प्रधान देश भी है। ❑❑

लेखक– कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी, दिल्ली

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)**
में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

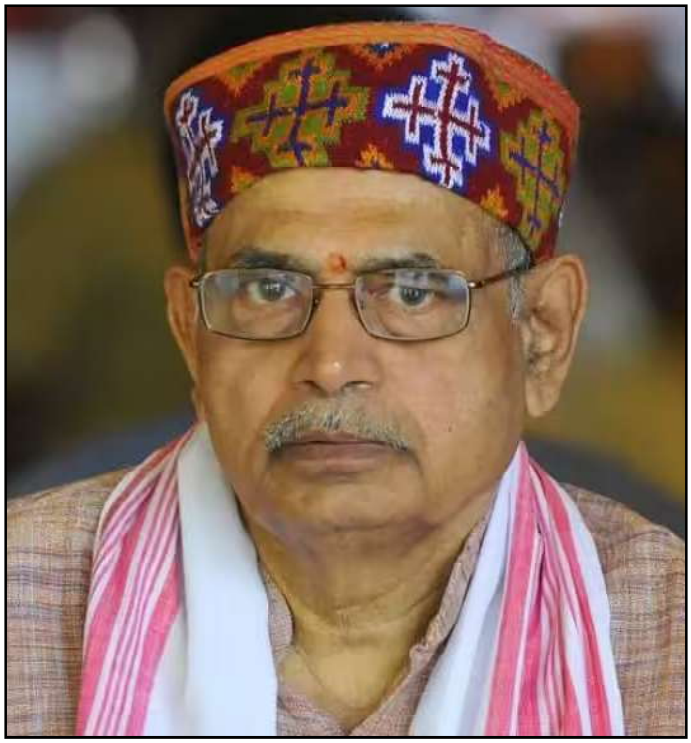

स्वदेशी को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने वाले मदन दास देवी जी

मदन दास देवी, जिन्हें उनके अनुयायी, प्रशंसक और साथी मदन जी के रूप में संबोधित करते थे, की उपस्थिति ऐसी थी कि आप वहाँ सबसे जटिल मुद्दों के समाधान की भी उम्मीद कर सकते थे। कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध मदन दास जी को उनके अनुशासन, उनकी ईमानदारी, उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को इस बात के लिए बहुत सम्मान मिला कि उनके उनके सान्निध्य मात्र से ही समाधान की संभावना स्पष्ट थी। इस राष्ट्र के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने सबसे कठिन समय में स्वदेशी को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया। आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी नींव मदन जी के 'आर्थिक राष्ट्रवाद' से पड़ी। इस विचार को उनके नेतृत्व में एबीवीपी में गढ़ा और प्रचारित किया गया।

9 जुलाई, 1942 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे मदन जी एम.कॉम, एलएलबी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आरएसएस के प्रचारक बने और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वे 1970 और 1992 के बीच वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे; और उसके बाद वर्तमान सरकार्यवाह, दत्तात्रेय होसबोले ने वहां उनसे कमान ली।

श्रद्धेय शेषाद्री जी, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी, प्रो. एमजी बोकरे और अन्य नेताओं के साथ, 1991 में गठित स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक सदस्यों में से वे एक थे; और उस समय उन्होंने मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व लिया। यह लड़ाई पश्चिमी दुनिया द्वारा चलाए जा रहे वैश्वीकरण और भारत को महज एक बाजार के रूप में विकसित करने के खिलाफ थी। जहां दत्तोपंत ठेंगड़ी स्वदेशी को वैचारिक अधिष्ठान प्रदान कर रहे थे, मदन दास देवी जी, पहले एबीवीपी के प्रतिनिधि के रूप में और फिर बाद में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से संरक्षक के रूप में, लगातार स्वदेशी जागरण मंच की संचालन समिति में रहते हुए मंच का मार्गदर्शन करते रहे। प्रारंभिक वर्षों से, उस समय तक जब स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक ताकत बना, मुद्दों को उठाने और विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने के साथ, वे हमेशा मंच के मामलों की धुरी में रहे। मंच के सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों पर मदन दास जी की छाप आज भी दिखती है। डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के गठन से पहले विवादास्पद डंकल ड्राफ्ट के विरोध को रूप देने से लेकर, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे; और बाद में 'सिंगापुर' मुद्दों पर जब विकसित देश श्रम मानकों, पर्यावरण मानकों, लिंग (जेंडर) जैसी नई शर्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके सक्षम मार्गदर्शन के तहत इसका पुरजोर विरोध किया गया। बाद में जब महाराष्ट्र में बिजली क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज कंपनी एनरॉन को लाने का प्रयास किया गया, तो उनके मार्गदर्शन में इस परियोजना का पुरजोर विरोध हुआ और अंतोत्गत्वा देश इसे रोकने में सफल रहा।

जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सहयोगियों के साथ केंद्र में सत्ता की बागडोर संभाली और सरकार में ऐसे नेता भी थे, जो स्वदेशी विचारधारा के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं रखते थे, मदन दास जी उस सबसे कठिन समय में चट्टान की तरह खड़े रहे। यही वह समय था जब मदन दास जी को सह सरकार्यवाह के रूप में सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच समन्वय स्थापित करने का काम सौंपा गया था। कई विवादास्पद मुद्दे सामने आए, जिससे स्वदेशी जागरण मंच और सरकार आमने–सामने हो गए। इनमें एनरॉन, डब्ल्यूटीओ, बीमा में एफडीआई, विनिवेश जैसे कुछ मुद्दे शामिल हैं। उन दिनों डब्ल्यूटीओ के विभिन्न मुद्दों पर 2003 में स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महाधरना आयोजित किया, जिसने डब्ल्यूटीओ में भारत सरकार के दृष्टिकोण को बदला और श्री अरुण जेटली, जो उस समय भारत के वाणिज्य मंत्री थे, ने डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सुझाये वे सब मुद्दे उठाए, जिनकी विकासशील देशों ने खासी सराहना की। उसी कालखंड में बीमा क्षेत्र में एफडीआई खोलने के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आंदोलन किया गया, जिसके कारण सरकार को बीमा में एफडीआई को केवल 26 प्रतिशत तक सीमित करने के संसदीय संकल्प को अपनाना पड़ा। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमें मिलते है, जहां मदन दास जी के मार्गदर्शन में स्वदेशी जागरण मंच के सामूहिक नेतृत्व द्वारा देशहित में ऐसे अनेक मामले उस कालखंड में और उसके बाद भी उठाए, जिससे देश की दिशा और दशा दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वो एक ऐसा कालखंड था, जिसमें मदन दास जी पर दोहरा दायित्व था, कि एक ओर उन्हें स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों, जिनके निर्माण में उनकी भूमिका थी, और जिसे उन्होंने पुष्ट किया था, के मुद्दों पर सहयोग देना था, तो दूसरी ओर मंच सहित इन संगठनों और वाजपेयी सरकार के बीच संतुलन स्थापित करना था। यह सब काम उन्होंने अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता से किया।

मदन जी के सक्षम मार्गदर्शन के कारण, कई मुद्दों को उठाया गया और बाद में अंततः सुलझा लिया गया। उनके माध्यम से जो कुछ कहा और किया गया, उसके कारण स्वदेशी जागरण मंच को एक दुर्जेय शक्ति के रूप में जाना जाने लगा, वे उस परिस्थिति के रचयिता कहे जा सकते हैं।

उन दिनों से, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, स्वदेशी जागरण मंच राजनीतिक व्यवस्था की परवाह किए बिना, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाता रहा है, जो मंच को अलग पहचान देता है। मदन जी ने इसकी नींव रखी थी। और शायद, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं मुद्दों को लागू कराने के लिए आज तत्परता से कार्य कर रहे हैं। ❑❑

2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारतः सतीश

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं देश की युवाशक्ति को जानता हूं। साल 2040 तक दुनिया की यह पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आज आर्थिक प्रगति की रफ्तार भारत की सबसे ज्यादा है लेकिन, वहीं जब बेरोजगारी की बात आती है तो यह जी–20 देशों में पिछले पायदान पर खड़ा आता है, यह एक बड़ी समस्या है।

उन्होंने एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री म.प्र. में हुए कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा में कहा कि अभी युवाओं और समाज की सोच रोजगार को लेकर है कि नौकरी हो, वह भी सरकारी। जबकि स्वरोजगार की तरफ जाना होगा, मैन्यूफैक्चरिंग के लिए कदम बढ़ाना होगा, अपनी मानसकिता को बदलना होगा। आज हमे खूब स्टार्टअप खड़े करने हैं, स्वरोजगार में जाना है। हमारे युवा तेजी से इस सेक्टर में मैन्यूफैक्चरिंग में जा रहे हैं। इसलिए हमने स्वावलंबी भारत अभियान चलाया है, क्योंकि देश में हर महीने 9 लाख युवा रोजगार के लिए आ रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार देना सरकार के बस में नहीं है।

मुफ्त की घोषणाओं को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बातें सरकार और राजनीतिक दलों की है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, राजनितिक दल अपने हिसाब से यह करते है, जिस समय चुनाव होता है। इसमें कुछ भी ठीक और कुछ भी गलत नहीं होता, हम पॉजीटिव कैंपेन कर रहे हैं हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। राजनीतिक दल तो सभी कहते हैं कि हमें सत्ता में लाओ हम रोजगार देंगे, लेकिन 70 सालों में तो बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। दल और सरकार यह दूर नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसलिए यह अभियान चलाया है।

उन्होंने जीएसटी से रोजगार बढ़ने या घटने के सवाल पर कहा कि जीएसटी ग्रैंड सक्सेस है। इसने इनफार्मल इंडस्ट्री को फार्मल रूप दिया है, पहले जो टैक्स 90 हजार करोड़ प्रति माह था वह 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे देश में रोजगार में काफी मदद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार छोटी होना चाहिए उन्हें बिजनेस, मैन्यूफैक्चरिंग में नहीं आना चाहिए, एयर इंडिया वह क्यों चलाएं, अब निजी हाथों में है तो प्रॉफिट में आ गई है। सरकार जितनी छोटी होगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी।

https://thesootr.com/state/rss-official-said-before-modi-i-give-guarantee-of-third-big-economy/44678

युवा पीढ़ी को जागरूक होने की जरुरत है

शहर के गोसाईबाग स्थित माहुरी मंडल भवन में स्वावलंबी भारत अभियान दक्षिण बिहार स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले एक दिवसीय "प्रांतीय विचार वर्ग' पर सेमिनार का आयोजन किया गया। शुरुआत स्वावलंबी भारत अभियान के गीत से हुई। चार सत्रों में चले इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत और महिलाओं की भागीदारी पर अधिकांश विचार केंद्रित रहा। वक्ताओं ने दोनों विषयों पर अपने विचार रखे। कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर वर्ग का साथ जरूरी है। महिलाओं को भी अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। बेरोजगार युवा पीढ़ी भी जागरूक हों। वे अपनी मानसिकता को बदलें।

बता दें कि स्वावलंबी भारत अभियान के तहत रोजगार सृजन केन्द्र द्वारा भारत को बीपीएल मुक्त, युवाओं को रोजगार युक्त करने के लिए एक दिवसीय मंथन सुबह नौ बजे से लेकर शाम छह बजे तक चला। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक सुभाष वर्मा एवं रंजीत बरहपुरिया, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, विद्या भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सहकार भारती, लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, शिक्षण मंडल सहित कई समूहों के लोग शामिल हुए।

इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक अरुण ओझा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय उपाध्याय, अखिल भारतीय स्वदेशी मेला के संयोजक सचिंद्र

बरियार, संयोजक अमरेंद्र सिंह, संयोजक यदुनंदन प्रसाद, आयोजन प्रमुख जितेंद्र कुमार मिश्र, डॉ संजीव कुमार सिंह, रोजगार सृजन केंद्र के संयोजक सुमंत कुमार, लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार बीरेन्द्र कुमार सिंह, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौशलेन्द्र सिंह, आदि मौजूद थे।

https://www.bhaskar.com/local/bihar/gaya/news/unemployed-young-generation-needs-to-be-aware-change-your-mindset-131547907.html

स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा देशः पटेल

स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर परिवार, समाज प्रदेश और राष्ट्र के विकास में सहयोग करने की भावना को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण का कार्यक्रम कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय बिश्रामपुर में स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक जगदीश पटेल ने सरगुजा संभाग की बैठक में अपना विचार व्यक्त करते हुए ये बातें कहीं। बैठक का शुभारंभ भारत माता व स्वदेशी जागरण मंच के जनक राष्ट्र ऋषि दंतोपत ठएगड़ी के छायाचित्र के समक्ष दीप जलाकर किया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव ने कहा कि छत्तीसगढ़ से अधिक संख्या में पलायन हो रहा है। यदि हम सब अपने ग्राम, नगर और प्रदेश वासियों को स्वदेशी के साथ जोड़ें, तो उनके आसपास उनके घर में ही बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जिससे उनका जीविको पार्जन हो सकता है। इससे वे और भी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। इसके लिए मिलकर प्रयास करना होगा।

https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/jashpur/news/the-country-is-moving-from-swadeshi-to-self-reliance-patel-131514447.html

पारम्परिक सोच से बाहर आएंगे तभी तरक्की करेगा उद्योग–व्यापार

उद्योग एवं व्यापार को आगे बढाना है तो इनोवेशन एवं तकनीकी उन्नयन के साथ विजन को ब्रांड रखना होगा। पारम्परिक सोच से बाहर आकर नवीन आयडिया लाने होंगे तभी देश का उद्योग एवं व्यापार तरक्की करेगा। यह बात स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने कही। वे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के सभागृह में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उद्यमिता प्रोत्साहन एवं संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि आपने कहा कि आज भारत की युवा आबादी विश्व में गोथ स्टोरी लिख रही है तथा विश्व में महारत हासिल कर रही है। श्री कुमार ने सभी उद्योगजनों से नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित कर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सभी उपस्थिति उद्योगपतियों से विचार भी जाने और उनके प्रतिउत्तर में पारम्परिक सोच से बाहर निकलने का मार्ग भी बताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने अपने स्वागत ने अपने उद्बोधन में इंडस्ट्री एकेडमिया को जोडने एवं युवाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने की. इस अवसर पर उद्योगों के इंदौर के उद्योग एवं व्यापार के उन्नयन हेतु अपने उपस्थित रहे। अपने सुझाव भी रखें जिनमें सर्वश्री हरीश नागर, प्रमोद डफरिया, सुनीता जैन, श्रेष्ठा गोयल, अनुजा पुरोहित, सुरेश नुहाल, अमित संचेती, संतोष वागले. शिवनारायण शर्मा आदि सुझाव दिये. एसोसिएशन की ओर से उद्योग एवं व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया, जिनमे मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स से अजीत सिंह नारंग, दाल मिल उद्योगपतियों और एसोसिएशन, प्रिंटिंग पैकिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन, पोलोग्राउंड एसोसिएशन, सराफा व्यवसाई संगठन, सियागंज किराना व्यापारी संघ, आयुर्वेद एसोसिएशन के राजेश सेठिया व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन तरूण व्यास एवं विशाल पुरोहित ने किया। एसोसिएशन ने उपस्थित अतिथियों में श्री केशव दुबोलिया, हरिओम वर्मा, डॉ सुरेश चोपड़ा, धर्मेन्द्र दुबे, दिलीप सिंह चौहान आदि को स्मृति चिन्ह भेंट किये। कार्यक्रम में आलोक दवे, दिलीप देव, प्रमोद जैन, अनिल पालीवाल, गिरीश पंजाबी, राजेश मिश्रा, हेमेंद्र बोकड़िया, रविकांत द्विवेदी आदि बडी संख्या में महिला उद्यमियों ने सहभागिता की।

पिछड़ गया अमरीका और चीन, भारत का दुनिया में डंका

एक ओर जहां रेटिंग एजेसिंया अमेरिका और चीन जैसे देशों की रेटिंग घटा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनका भारत पर भरोसा कायम है। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से अच्छी खबर आई है। दरअसल, एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है। वहीं चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है।

भारत के बढ़ते कदमों पर तमाम एजेंसियों के भरोसे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मॉर्गन स्टैनली ने महज चार महीने के भीतर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग को इक्वलवेट किया गया था और अब ये रेटिंग एक बार फिर से बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने ये उम्मीद भी जताई है कि भारती य अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करेगी।

ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ब्रोकरेज फर्म ने इसे कम करते हुए इक्वलवेट कर दिया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में विकास और वैल्यूएशन से जुड़ी हुई चिंताएं बरकरार हैं। इसके अलावा चीनी बाजारों में तेजी का सिलसिला भी रुकने लगा है। चीन के अलावा मॉर्गन स्टेनली ने ताइवान की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करते हुए इक्वलवेट कर दिया है।

मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत की रेटिंग को बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ होगा और बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने से बड़ी तेजी की संभावना है। भारत के अलावा कोरिया की रेटिंग को भी ओवरवेट किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया गया है. यहां ये जानना जरूरी है कि आखिर इक्वलवेट, ओवरवेट और अंडरवेट रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो बता दें ओवरवेट का मतलब होता है कि देश का मार्केट दूसरे बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं इक्वलवेट इस बात का संकेत देता है कि मार्केट का दूसरे बाजारों के बराबर प्रदर्शन करेगा। वहीं अंडरवेट रेटिंग मार्केट का दूसरे बाजारों से पिछड़ना होता है।

https://www.aajtak.in/business/news/story/morgan-stanley-upgrades-india-shares-to-overweight-downgrades-china-know-why-tutc-1749808-2023-08-04

सौदा रद्द होने के बाद झुक गया चीन

भारत– चीन के रिश्तों में तनातनी से हर कोई वाकिफ है। चीन की हरकतें भी भारत को असहज करती हैं लेकिन भारत के एक फैसले की वजह से चीन बैकफुट पर है. मामला बीवाईडी आटोमेकर से जुड़ा है। चीन की यह कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में नामी कंपनी है और भारत में एक बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहती है। सीधे तौर पर कहें तो भारत में एक प्लांट लगाना चाहती है लेकिन भारत ने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस मामले में चीन के शीर्ष राजनयिक ने एनएसए अजित डोभाल के साथ बातचीत में कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं हैं। नई दिल्ली यानी भारत सरकार फैसले पर दोबारा विचार करे।

वांग यी जो कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी में बड़े ओहदे पर और विदेश मंत्री से ऊपर माने जाते हैं, उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि हमें ऐसे नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है जो आपसी विश्वास को बढ़ाने वाले हो। दोनों देशों को आपसी सहमति और सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। दोनों शख्सियतों के बीच जोहांसबर्ग में ब्रिक्स सदस्यों की बैठक से इतर हुई। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वांग यी ने कहा कि भारत और चीन दोनों या एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े या विरोध में हों वैश्विक स्तर पर फायदा– नुकसान दोनों का है।

वांग यी ने कहा कि चीन पुरानी वैश्विक व्यवस्था पर चलने का हिमायती नहीं जिसमें किसी खास देश का प्रभुत्व होता था। चीन कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिसकी वजह से किसी खास देश की प्रभुता स्थापित हो। हम चाहते हैं कि विकासशील देश एक साथ मिलकर काम करें जिसमें भारत भी शामिल हो। चीन बहुपक्षीवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है।

पिछले हफ्ते भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में आकर्षक भारतीय बाजार में ईवी के साथ–साथ इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के चीनी ईवी दिग्गज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि विचार–विमर्श के दौरान भारत में चीनी निवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया गया। एक दूसरे अधिकारी ने मौजूदा दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस तरह का चीनी निवेश संभव नहीं है। वर्तमान में बीवाईडी की 2023 में भारतीय बाजार में ईवी की कम से कम 15,000 इकाइयां बेचने की योजना है। अस्वीकृति के बावजूद कंपनी भारत में अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने और विनिर्माण क्षमता को उन्नत करने की योजना बना रही है। ❑❑

https://zeenews.india.com/hindi/pakistan-china/china-bowed-down-from-action-on-byd-plant-deal-wang-yi-said-no-enmity-with-india/1794843

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से
स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

स्वतंत्रता दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

सचित्र झलक

बैठकें

संभाजी, देवगिरि

मुंबई, कोंकण

कर्णावती, गुजरात

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अगस्त 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

इंदौर, म.प्र.

नागपूर, विदर्भ प्रांत

राजकोट, गुजरात

वर्धा, महाराष्ट्र

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती